नई दिल्ली

28

अगस्त, 2026

शुक्रवार

मूल्य : 01 रुपए

पृष्ठ : 08

वर्ष : 14

अंक : 148

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

भारतीय टीम के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाना कठिन होगा : द्रविड़ 07

संक्षिप्त वार्ता

जबलपुर में 472 करोड़ से टी-72 टैंकों की ओवरहॉलिंग

जबलपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में ळ-72 टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमिपूजन किया। करीब 472 करोड़ रुपए की लागत से यहां भारतीय सेना के ळ-72 टैंकों की मरम्मत, जांच और तकनीकी अपग्रेड के लिए सुविधा तैयार की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

नई सुविधा के तहत व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में हर साल 80 टी-72 और ळ-90 टैंकों के ओवरहॉल की अतिरिक्त क्षमता विकसित की जाएगी। भारतीय सेना को हर साल करीब 230 T-Series टैंकों के ओवरहॉल की जरूरत होती है। अभी हेवी व्हीकल फैक्ट्री , अवाडी में करीब 150 टैंकों के ओवरहॉल की क्षमता है। जबलपुर की 80 टैंकों की अतिरिक्त क्षमता जुड़ने के बाद कुल क्षमता 230 टैंक प्रतिवर्ष हो जाएगी।

व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने नई परियोजना से पहले टी-72 टैंकों के ओवरहॉल का पायलट प्रोजेक्ट किया था। फैक्ट्री ने दो ळ-72 टैंकों का ओवरहॉल पूरा कर उन्हें भारतीय सेना को सौंपा। इस दौरान टैंकों की तकनीकी जांच, मरम्मत और आवश्यक पुर्जों को बदलने का काम किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन जमीनी युद्ध में टी-72 और टी-90 टैंकों की भूमिका जरूरी है।

देश के बारिश का असमान वितरण अभी भी चिंता का विषय: विशेषज्ञ

वेब वार्ता, नई दिल्ली

हाल के दिनों में देश भर में हुई बारिश से खरीफ फसलों को व्यापक नुकसान होने की आशंका कम हुई है। इस वजह से कृषि क्षेत्र के लिए राहत की स्थिति बनी है। इसके बावजूद कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का असमान वितरण अभी भी चिंता का विषय है और आने वाले समय में इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी।

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी की रिपोर्ट के अनुसार, 19 अगस्त तक देश में संचयी वर्षा की कमी घटकर 12.6 प्रतिशत रह गई, जबकि जून में यह कमी करीब 35 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है, हालांकि वर्षा का स्तर अभी पूरी तरह सामान्य स्थिति में नहीं पहुंचा है। मानसून में आए इस सुधार का सकारात्मक असर खरीफ फसलों की बुवाई पर भी दिखाई दे

रहा है। सीजन की शुरूआत में कमजोर बारिश के कारण खरीफ बुवाई प्रभावित हुई थी, लेकिन बाद में वर्षा बढ़ने के साथ बुवाई की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, 14 अगस्त तक कुल खरीफ बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में केवल 2 प्रतिशत कम रही, जबकि जून के अंत तक यह अंतर 21 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इससे साफ है कि बारिश में सुधार के साथ किसानों ने बुवाई की रफ्तार तेज की है। फसलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो धान का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 3.7 प्रतिशत कम रहा है, जबकि मक्का का रकबा करीब 4 प्रतिशत घटा है। दूसरी ओर दलहन, तिलहन, गन्ना और कपास जैसी फसलों का रकबा पिछले साल के स्तर के करीब बना हुआ है और इनमें अंतर लगभग 1 प्रतिशत के दायरे में है।

...जरूरत बताई गई है

मैक्वायरी का कहना है कि बुवाई में जो कमी अभी बची हुई है, वह कुछ चुनिंदा फसलों तक सीमित है और इसका असर व्यापक कृषि क्षेत्र पर नहीं पड़ रहा है। रिपोर्ट में जलाशयों में मौजूद पर्याप्त जल भंडारण को भी कृषि के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बताया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात के जलाशयों में पानी का भंडार 10 वर्ष के औसत के बराबर या उससे अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में जल भंडारण अपने संबंधित औसत स्तर के करीब 80 से 100 प्रतिशत तक बना हुआ है। हालांकि बिहार और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों की स्थिति पर विशेष नजर रखने की जरूरत बताई गई है।

नेपाल संकटः भारत ने फिर भेजी 35 टन राहत सामग्री, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भी हैं तैयार

वेब वार्ता, नई दिल्ली। नेपाल में तिब्बत सीमा के पास आई भीषण तबाही के बाद भारत ने राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। भारत ने गुरुवार सुबह दिल्ली के हिंडन एयरबेस से सी-17 सैन्य परिवहन विमान से 35 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है। विमान सुबह करीब 9 बजे रवाना हो गया। यह राहत अभियान भारत की तरफ से भेजी जा रही अतिरिक्त मानवीय सहायता का हिस्सा है।

बता दें इससे पहले भारत ने बुधवार रात को ही राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल भेजी थी। भारतीय वायुसेना के सी-130जे विमान से करीब 10 टन मानवीय सहायता और जरूरी मेडिकल सामान काठमांडू पहुंचाया। इसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाइयां शामिल थीं। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड से अब तक कम से कम 163 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर भारतीय हैं। बाढ़ ने नेपाल-तिब्बत सीमा से जुड़े इलाकों में भारी तबाही मचाई है। कई जगह सड़क, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहत सामग्री भेजने से पहले पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की थी। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों के प्रति एकजुटता जताते हुए हर संभव मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की टीमें नेपाल में राहत और बचाव प्रयासों के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ करीबी समन्वय कर रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने नेपाल के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ जरूरी दवाइयां भी भेजी हैं। भारतीय वायुसेना ने बताया कि सी-17 और सी-130 विमानों के जरिए आगे भी राहत सामग्री भेजी जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टरों को रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास भी राहत प्रयासों में सहयोग कर रहा है।

कुलगाम में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, 5 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार

कुलगाम। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। बुगाम बाग इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने पांच कथित आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।

अधिकारियों ने मीडिया को बताया है, कि यह संयुक्त अभियान कुलगाम पुलिस, 9 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 18वीं बटालियन ने चलाया। अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से चार 9 एमएम पिस्तौल, चार मैगजीन, 22 राउंड गोला-बारूद और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई को क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। अधिकारियों ने बरामद हथियारों और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गिरफ्तार आरोपियों का आतंकियों से किस तरह का संपर्क था और बरामद हथियारों का इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया जाना था।

रूस के प्लांट में लगी भीषड़ आग, सात की मौत, नौ लापता

मॉस्को। रूस के सुदूर पूर्वी अमूर इलाके में एक विशाल गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें भीषण आग लगने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में छह चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं, जबकि नौ अन्य चीनी कर्मचारी अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

राजस्थान हाईकोर्ट में जजों का विवाद: जज संजीव ने हाईकोर्ट सीजेआई को दिया नोटिस

सूर्यकांत ने कहा- इस मसले को केवल स्थापित संस्थागत तंत्र के जरिए ही निपटाया जाए

नई दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जस्टिस शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को चिट्ठी लिखी है। इसमें जस्टिस संजीव प्रकाश पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि इस मसले को केवल स्थापित संस्थागत तंत्र के जरिए ही निपटाया जाना चाहिए।

जस्टिस मेहता ने सीजेआई को लिखे तीन अलग-अलग पत्रों में जस्टिस संजीव प्रकाश के अधीन गंभीर प्रशासनिक अनियमितताएं होने और चुनिंदा मामलों को

सूचीबद्ध किए जाने का आरोप लगाया है। देश की सर्वोच्च अदालतों के जजों के बीच इस विवाद ने एक पुराने मामले का याद ताजा कर दी है। उस विवाद में एक जज की गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई थी। मामला 2016 का है। साल 2016 में न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक मामला मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस सीएस कर्णन से जुड़ा था। उन्होंने तत्कालीन सीजेआई टीएस ठाकुर की ओर से अपने तबादले की सिफारिश को ही रोकने का आदेश जारी कर दिया था। दरअसल, जस्टिस कर्णन का तबादला मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट करने की सिफारिश की गई थी। 12 फरवरी 2016 को उन्हें इस संबंध में प्रस्ताव मिला, लेकिन जस्टिस कर्णन इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने 15 फरवरी को एक आदेश जारी किया था इसमें उन्होंने सीजेआई की ओर से उनके तबादले की सिफारिश पर ही रोक लगा दी।

यह मामला इसलिए असाधारण था क्योंकि एक हाईकोर्ट के मौजूदा जज ने देश के प्रधान न्यायाधीश के प्रशासनिक फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सीजेआई से इस तबादले की वजह बताने को कहा और इसके लिए लिखित जवाब मांगा था। जस्टिस कर्णन ने अपने आदेश में तत्कालीन सीजेआई से कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में दखल न दिया जाए।

क्या बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव के बाद अब कैबिनेट में भी होगा फेरबदल ?

अभी काउंसिल में पीएम मोदी समेत 69 सदस्य, 12 पद अभी भी खाली

वेब वार्ता, नई दिल्ली। बीजेपी का संगठनात्मक बदलाव अब पूरा हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने 65 सदस्यों वाली नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के साथ ही, राजनीतिक ध्यान अब मोदी सरकार पर केंद्रित हो गया है कि क्या पार्टी के संगठनात्मक बदलाव के बाद अब कैबिनेट में भी कोई बड़ा फेरबदल होगा। अभी काउंसिल में पीएम समेत 69 सदस्य हैं। संविधान के तहत सदस्यों की संख्या 81 हो सकती है यानी 12 पद अभी भी खाली हैं।

सूत्रों के मुताबिक इन बदलावों पर 2029 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले कुछ विधानसभा चुनावों का असर दिखेगा। हालांकि, सिर्फ राजनीतिक वजहें ही अहम नहीं होंगी, क्योंकि लीडरशिप उन मंत्रियों का बोझ भी कम करना चाह सकती है जिनके पास कई विभाग हैं। बीजेपी अब कई अहम विधानसभा चुनावों और उनके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। नई टीम में कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जो युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने और चुनावों पर ज्यादा ध्यान देने का संकेत है। अब सरकार में भी ऐसे ही बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

हाल ही में तीन बदलाव हुए हैं। पेपर लीक को लेकर युवाओं के विरोध के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पद छोड़ दिया। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने पर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी में नई भूमिका निभाने वाले नेताओं की बारी आ सकती है। इनमें वे राज्यमंत्री शामिल हैं जिन्हें संगठन में काम सौंपा गया है। हाल ही में हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पार्टी की राज्य इकाई का प्रमुख बनाया गया है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि संभावित

फेरबदल में चुनावी जरूरतों, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, उम्र, कामकाज और बीजेपी के एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत को ध्यान में रखे जाने की उम्मीद है। बीजेपी की नई टीम में सबसे अहम नामों में से एक पीयूष गोयल हैं, जिन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। गोयल अभी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इसलिए बीजेपी के एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत के हिसाब से उनकी नई संगठनात्मक जिम्मेदारी काफी अहम है।

संगठन में वापसी हुई है

गोयल अकेले ऐसे बड़े राजनीतिक चेहरे नहीं हैं जिन्हें नई भूमिका दी गई है। बीजेपी की सबसे जानी-मानी राष्ट्रीय नेताओं में से एक और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी की भी पार्टी संगठन में वापसी हुई है। बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव प्रचार मशीनरी के साथ उनके लंबे जुड़ाव और पार्टी में उनके कद को देखते हुए, उनका शामिल होना राजनीतिक रूप से काफी अहम है। बीजेपी ने इस अटकलबाजी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पार्टी आम तौर पर एक व्यक्ति-एक भूमिका के नियम का पालन करती है, जिन नेताओं के नाम मंत्री बनने की अटकलों में थे, उन्हें इसके बजाय संगठन में जिम्मेदारी दी गईं जैसे स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, सतीश पूनिया और तरुण चुघ।

कुकू कोहली के निधन पर सलमान खान ने जताया दुख, परिवार को दी सांत्वना

वेब वार्ता, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशक कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था वह 77 साल के थे। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार को मुंबई में हुए उनके अंतिम संस्कार में हिंदी सिनेमा के कई बड़े सितारों ने पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी कुकू कोहली के निधन पर गहरा दुख जताया है।

सलमान खान ने एक्स पर लिखा- ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे कुकी जी,

अरुणा जी, इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपको यह दुख सहने की हिम्मत दे। बता दें कुकू कोहली अपने पीछे पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस अरुणा ईरानी को छोड़ गए हैं। इसके अलावा उनकी पहली पत्नी रीता कोहली से उनकी दो बेटियां पूजा और करिश्मा भी हैं। कुकू कोहली वही डायरेक्टर हैं, जिन्होंने साल 1991 में आई सुपरहिट फिल्म फ्हाफूल और कांटेह्न से अजय देवगन को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। अजय के करियर को नई दिशा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने गुरु को याद करते हुए अजय देवगन ने भावुक पोस्ट में लिखा- कुछ लोग आपकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देते हैं। कुकू जी मेरे लिए उन्हीं में से एक थे। आपकी कमी बहुत खलेगी कुकू जी। ओम शांति।

तुलजा भवानी मंदिर की सुरक्षा बढ़ी, एमएसएफ के 116 जवान तैनात

मुंबई। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तुलजा भवानी मंदिर में त्योहारों के मौसम से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सुरक्षा बल (एमएसएफ) के 116 कर्मियों को तैनात किया गया है। धाराशिव जिले के तुलजापुर स्थित इस मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर न्यास की ओर से मीडिया में जारी विज्ञप्ति के अनुसार, एमएसएफ के दल में एक निरीक्षक और चार पुलिस उपनिरीक्षकों समेत छह अधिकारी शामिल हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने मंगलवार को तुलजापुर शहर में मार्च भी किया। मंदिर प्रशासन के मुताबिक, त्योहारों और लगातार पड़ने वाली छुट्टियों के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए एमएसएफ के अधिकारियों और जवानों को सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई है।

नेपाल-चीन सीमा पर फिर मंडराया जलप्रलय का खतरा

बीजिंग। नेपाल में भीषण बाढ़ से मची तबाही के बीच चीन-नेपाल सीमा पर एक और बड़े जलप्रलय का खतरा मंडराने का अंदेशा जताया जा रहा है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास प्राकृतिक अवरोध के कारण एक बड़ी बैरियर झील बन गई है। गुरुवार सुबह तक इसमें करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और झील के ओवरफ्लो होने की स्थिति बनी हुई है। अनुमान है कि अगले तीन दिनों में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी पहुंच सकता है। ऐसे में कुल जलभराव करीब 50 लाख घन मीटर तक पहुंचने की आशंका है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने गुरुवार को तिब्बत में नेपाल सीमा के पास ग्यीरोंग टाउनशिप का दौरा किया।

नेपाल की भीषण बाढ़ में बह गए 12 हजार करोड़

वेब वार्ता, काठमांडू

नेपाल में हाल ही में आई भीषण बाढ़ को पिछले 33 वर्षों की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक माना जा रहा है। इस जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, 133 भारतीयों सहित 1000 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा से अंदाजन 200 बिलियन नेपाली रुपये, यानी करीब 12 हजार करोड़ भारतीय रुपये से अधिक के बुनियादी ढांचे का नुकसान हो चुका है। यह भयावह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब तिब्बत की सीमा के पास एक भूकंप आया। अधिकारियों का मानना है कि भूकंप के झटकों

की वजह से ग्लेशियल लेक फटा होगा, जिससे पानी का बहाव तीव्र गति से नदियों में आ गया। भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा, जिससे तिब्बत से लगे रसुवा और धादिंग जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए।

इसके बाद बाढ़ का पानी नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुं और नवलपरासी पूर्व जैसे अन्य जिलों में फैल गया, जिसने राजधानी काठमांडू से लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूर तक के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार, अचानक आई बाढ़ में 157 शव बरामद किए गए हैं। नेपाल सरकार ने लगभग 500 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। चीन के सीमावर्ती हिस्से में भी तीन लोगों की मौत हुई और 265 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है।

नेपाल से सामने आए कई वीडियो इस तबाही की भयावहता को बयां करते हैं। इन वीडियो में कीचड़, चट्टानों और मलबे से भरा पानी तेज रफ्तार से बहता दिखाई दिया, जिसने इमारतों और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। एक वीडियो में एक चार मंजिला इमारत को पल भर में बहते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे वीडियो में पानी के जबरदस्त दबाव से एक लंबा पुल टूटता हुआ नजर आया। कई पुल तेज बहाव के कारण ढह गए। भारत ने इस मुश्किल घड़ी में नेपाल को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और मानवीय सहायता का आश्वासन दिया।

भारत ने पड़ोसी देश को राहत सामग्री की पहली खेप भी भेज दी है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और नेपाल सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है।

नेपाल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का जताया आभार

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने देश में आई भीषण बाढ़ के बीच एकजुटता जताने और बचाव एवं राहत कार्यों के लिए हरसंभव मानवीय सहायता की पेशकश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पीएम शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत और उनकी ओर से व्यक्त की गई संवेदनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। पीएम बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा, कि इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के प्रति भारत की एकजुटता और सहायता की पेशकश की वे दिल से सराहना करते हैं।

संपादकीय

नीति आयोग के बंजर युवा

नीति आयोग की नई रपट आई है- विकसित भारत 2047 के लिए कौशल की पुनर्कल्पना। रपट में शिक्षा, रोजगार, युवा और उसकी उत्पादकता आदि पर ऐसे खुलासे किए गए हैं, जिनसे लगता है कि हमारी अधिकतर युवा जमात बंजर है। वह देश के कार्यबल का हिस्सा नहीं है। बेशक बेरोजगारी एक भयानक समस्या है, लेकिन शिक्षा पर भी कई सवालिया निशान हैं। रपट के मुताबिक, 15-29 साल के आयु-वर्ग के 8.70 करोड़ युवा ऐसे हैं, जो न तो पढ़ रहे हैं और न काम कर रहे हैं और न ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनमें से करीब 58 फीसदी घरेलू काम में व्यस्त हैं। यानी घर पर बैठे हैं, जबकि यह उम्र सर्वाधिक उर्वर मानी जाती है। इनसान काम करता है और अपने तथा देश के लिए संसाधन पैदा करता है। इसे ही जनसांख्यिकीय लाभांश माना जा सकता है। देश की 65 फीसदी आबादी की उम्र 35 साल से कम है, सिर्फ यही जनसांख्यिकीय लाभांश का आधार नहीं हो सकता। रपट के मुताबिक, 8.25 फीसदी युवा स्नातक को ही उनकी शिक्षा और डिग्री के अनुकूल काम मिल पाता है। शेष की पढ़ाई को नौकरी के लायक नहीं समझा जाता, लिहाजा यह उद्योगपतियों और नियोक्ताओं के लिए भी भारी समस्या है कि युवा हुनरमंद नहीं है। उनकी डिग्री महज कागज का टुकड़ा है। बेरोजगार स्नातक 13 फीसदी हैं, जबकि महिला स्नातकों में बेरोजगार 20.4 फीसदी हैं। देश का कुल कार्यबल (काम करने वाले) 65.4 करोड़ है। सिर्फ 14.19 फीसदी को ही नियमित वेतन या मजदूरी नसीब है। गैर-कृषि क्षेत्र में करीब 27 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं है। सबसे डरावना और सवालिया आंकड़ा यह है कि केंद्र सरकार में 8,23,556 सरकारी पद खाली पड़े हैं। सरकार इन पदों पर भर्तियां क्यों नहीं करती? यही हाल राज्य सरकारों का है, जहां लाखों सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं, लेकिन नौकरियां दी नहीं जा रही हैं। सरकारें आउटसोर्स करके ठेके पर नौकरियां देती हैं, ताकि अरबों का पेंशन का बोझ खत्म किया जा सके। यह भयावह सवालिया स्थिति है। रक्षा मंत्रालय में 2.41 लाख और रेलवे में 2.40 लाख से अधिक पद खाली हैं। क्या ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मंत्रालय पर्याप्त कार्यबल के बिना ही चलाए जा रहे हैं? यहां देश की सुरक्षा और गति-शक्ति का भी सवाल है। कदाचित यही कारण है कि देश के युवा, जेन-जी और जेन-अल्फा, उबल रहे हैं, आक्रोशित और आंदोलित हैं।

फिलहाल दिल्ली, भोपाल, पटना, रायपुर, लखनऊ, सागर (मप्र), सिरोही (राजस्थान) और महोबा (उप्र) आदि शहरों में युवा सड़कों पर हैं। विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस झेल रहे हैं, पानी की तेज बौछार उनकी गति को लड़खड़ा रही है। फिर भी वे अपने अधिकारों और व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। जब बाल-आयु में भैंस-गाय के तबेलों में स्कूल की कक्षाएं लगेंगी, मात्र 4 कमरों में 512 बच्चे ठूंस कर बिठाए जाएंगे, एक ही कथित अध्यापक सभी कक्षाओं को पढ़ाएगा, न स्वच्छ शौचालय, न पीने का पानी, न ही क्लास रूम में पंखे और डेस्क की व्यवस्था होगी, तो ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्या खाक शिक्षा और नौकरी हासिल होगी? जिन राज्यों में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां नौकरियां देने की घोषणाएं की जा रही हैं। मसलन-उप्र में आगामी 6 माह में एक लाख नौकरियां देने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने स्कूलों के कायाकल्प के लिए 1871 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की है। इसी तरह राजस्थान सरकार ने भी 12,500 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है। मप्र के बड़वानी में जेन जी ने 20 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला। ऐसे कई प्रयासों से जेन-जी ने सरकारों के खिलाफ हल्लाबोल के हालात पैदा कर दिए हैं। आश्चर्य यह है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी-दर 36.2 फीसदी संघशासित लक्षद्वीप में है, जबकि राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी-दर केरल और हरियाणा में है। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि कौशल-प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा के बाद का विकल्प मानने के बजाय स्कूली स्तर से ही शुरू किया जाना चाहिए। कक्षा 6-12 तक सामान्य रोजगार और उद्यमिता कौशल सिखाए जाने तथा कक्षा 9 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। शायद उनसे देश की सूरत बदल सकती है! यह भी सत्य है कि सभी युवाओं को सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकार को नवीन योजनाएं बनानी चाहिएं। अब हमें यह मानसिकता छोड़ देनी चाहिए कि रोजगार तो केवल सरकारी ही अच्छा होता है। प्राइवेट क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोग काम करके अपने और अपने परिवार के लिए रोजी-रोटी कमा रहे हैं।

पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गाँव से ग्लोबल तक भारत की नई खेल यात्रा

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नई खेलो इंडिया योजना का लक्ष्य गाँव से ग्लोबल तक यानि जमीनी स्तर से लेकर ओलंपिक स्तर तक खिलाड़ियों की पूरी विकास-श्रृंखला तैयार कर भारत को खेल महाशक्ति बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से भारतीय खेल संस्कृति को गाँवों, स्कूलों और सामान्य परिवारों तक पहुँचाया है। तो वहीं प्रतिभा पहचान, आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतर अधोसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर पर बढ़ते जोर ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक अधिक व्यवस्थित प्रतिभा विकास मार्ग तैयार किया है। ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहन, टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी व्यवस्थाओं को मजबूती तथा राष्ट्रीय खेल महासंघों और प्रशिक्षण संस्थानों पर बढ़ता निवेश इस सोच को दशार्ता है कि भारत की खेल शक्ति केवल कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की क्षमता को अवसर देने में निहित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का खेलों के प्रति यह दृष्टिकोण आज पदक जीतने वाले भारत के साथ स्वस्थ, आत्मविश्वासी, अनुशासित और विश्व मंच पर नेतृत्व करने वाले भारत की कल्पना को आकार देगा। जहाँ हर युवा विकसित भारत 2047 के निर्माण के महायज्ञ में अपनी सार्थक आहुति देगा।

व्यापक दृष्टिकोण के फलस्वरुप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी नई खेलो इंडिया योजना हेतु वर्ष 2026झ27 से 2030झ31 की अवधि के लिये 36,441 करोड़ राशि की मंजूरी प्रदान की है। इससे 10 गुना ज्यादा खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। यह केवल खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की योजना नहीं बल्कि भारत के युवा सामर्थ्य को खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, अनुशासन, तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक उत्कृष्टता से जोड़ने की एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय परियोजना है। अब लक्ष्य केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोज लेना नहीं बल्कि उन्हें प्रतिभा पहचान से प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, उच्च स्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और ओलंपिक तैयारी तक निरंतर सहयोग उपलब्ध कराना है। नई खेलो इंडिया योजना से मध्यप्रदेश को खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सार्थक प्रयास करेगा। प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमियां और पहले से संचालित 52 खेलो इंडिया सेंटर को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खेल प्रतिभा और क्षमता के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।

किसी भी खिलाड़ी की यात्रा का पहला पड़ाव अक्सर उसका विद्यालय और स्थानीय खेल मैदान होता है। यह वह स्थान हैं जहाँ बच्चा सीखता भी है, खेलता भी है और अपनी क्षमता पहचानता भी है। इसलिए खेलो इंडिया फीडर स्कूल और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय जैसी पहलें विद्यालयों को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि प्रतिभा पहचान और खेल विकास का आधार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत खेलो नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समाहित करते हुए शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर शारीरिक क्षमता, रचनात्मकता, अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना और समग्र व्यक्तित्व विकास से जोड़ने पर बल दिया गया है।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विशाल युवा आबादी है, लेकिन प्रतिभा और पदक के बीच की दूरी अक्सर पर्याप्त प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, खेल विज्ञान और अवसरों की कमी से निर्धारित होती है। लेकिन यह नई योजना इस अंतर को कम कर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रदर्शन हेतु तैयार करेगी। एथलीट विकास मार्ग को इस प्रकार परिकल्पित किया गया है कि प्रतिभा पहचान के बाद खिलाड़ी को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, नियमित प्रतिस्पर्द्धा, उच्च स्तरीय कोचिंग, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और ओलंपिक तैयारी की क्रमिक सुविधाएँ मिलती रहें। जिससे जमीनी प्रतियोगिताओं से शुरू होकर खेलो इंडिया और आगे टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम तक की प्रगति सुनिश्चित होगी।

इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स (इ-केआईएस) नई खेलो इंडिया योजना में शुरू की गई एक विशेष श्रेणी है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाना और देश के एथलीट विकास तंत्र का लगभग 10 गुना विस्तार करना है। अब भारत का लक्ष्य केवल चैंपियन खोजने का नहीं बल्कि चैंपियन तैयार करने की प्रणाली बनाने का है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र, मान्यता प्राप्त खेल अकादमियाँ, खेलो इंडिया केंद्र तथा सशस्त्र बलों की युवा खेल कंपनियाँ इस पूरी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय प्रतिभा को उसके खेल करियर के विभिन्न चरणों में आवश्यक अवसर और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में सहायक होगा। एक सशक्त राष्ट्र वह नहीं जिसमें कुछ महान खिलाड़ी हों बल्कि वह है जिसमें हर वर्ग को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले। इस योजना में फिट इंडिया मूवमेंट को व्यापक बनाने का उद्देश्य भारतीय समाज में सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। जहां खेल की भूमिका पदक से कहीं बड़ी हो जाती है। खेल बच्चों में अनुशासन, युवाओं में आत्मविश्वास, समुदाय में सहभागिता और समाज में स्वास्थ्य-संस्कृति को बढ़ावा देता है।

महिलाओं की खेलों में भागीदारी, सीमावर्ती एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक सुविधाएँ, मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध खेल-आधारित पहल तथा पैरा-एथलीटों और पारंपरिक खेलों को समर्थन ये सभी पहल खेल को समावेशी सामाजिक परिवर्तन के माध्यम में बदलेंगी।

पारंपरिक खेलों को आधुनिक खेल पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ना सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रतिस्पर्द्धात्मक खेल के बीच एक सार्थक सेतु बनेगा। इससे भारत की खेल पहचान केवल वैश्विक मानकों को अपनाने वाली नहीं बल्कि अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ने वाली बनेगी।

किसी खिलाड़ी को उत्कृष्टता तक पहुँचाने में प्रशिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी दृष्टि से राष्ट्रीय कोच प्रत्यायन बोर्ड जैसी व्यवस्था कोचिंग योग्यताओं के मानकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अब भविष्य का प्रशिक्षक केवल तकनीक सिखाने वाला प्रशिक्षक नहीं बल्कि खेल विज्ञान, पोषण, मनोविज्ञान, डेटा, प्रदर्शन विश्लेषण और खिलाड़ी कल्याण की समझ रखने वाला विशेषज्ञ होगा।

वर्तमान खेल केवल प्रतिभा और परिश्रम पर निर्भर नहीं है। आज स्पोर्ट्स साइंस, डेटा एनालिटिक्स, पोषण, रिकवरी, मनोविज्ञान, प्रदर्शन विश्लेषण और आधुनिक तकनीक खिलाड़ी की सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। एकीकृत डिजिटल खेल मंच की परिकल्पना इस परिवर्तन को और गति देगी। यदि प्रतिभा पहचान, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, खिलाड़ी का प्रदर्शन, खेल अवसंरचना और एथलीट सहायता एक डिजिटल व्यवस्था से जुड़े हों तो निर्णय अधिक डेटा-आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाए जा सकेंगे। जिससे भविष्य का खिलाड़ी केवल मैदान पर मेहनत नहीं करेगा बल्कि विज्ञान और तकनीक उसके प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने में साथ देंगे।

नई खेलो इंडिया योजना का प्रभाव केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ी हुई योजना है। यह योजना वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों से लेकर भविष्य के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की आकांक्षा तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प तक, खेल भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

एक ऐसा भारत, जहाँ गाँव का प्रतिभाशाली बच्चा अपने सपने को केवल सपना न समझे बल्कि उसके पास उसे पूरा करने का स्पष्ट मार्ग हो जो उसे वैश्विक मंच तक पहुँचने का माध्यम बनें।यह केवल खेल नीति नहीं बल्कि भारत के युवाओं के सामर्थ्य को पहचानने, उसे अवसर देने और राष्ट्र निर्माण की शक्ति में बदलने का संकल्प है।

निश्चित रुप से प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की यह नई खेल यात्रा पदक जीतने के साथ खेल शक्ति से युवा शक्ति और युवा शक्ति से विकसित भारत के निर्माण की यात्रा बनेगी।

लेखक- विश्वास कैलाश सारंग
(मंत्री, म.प्र. शासन)

नर्सिंग छात्रों के साथ 5 साल से खिलवाड़, जिम्मेदार कौन ?

मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा पिछले पांच वर्षों से ऐसी उलझी पड़ी है, जिसका सिरा तलाश करते-करते विद्यार्थी थक गए। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में उलझी होने के कारण इसकी पूंछ का सिरा भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। व्यवस्था में सुधार होने की कल्पना करना भी अब व्यर्थ लगने लगा है। कभी नर्सिंग काउंसिल कटघरे में खड़ी दिखाई देती है, कभी विश्वविद्यालय, कभी सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में आती हैं। कभी कॉलेजों के निरीक्षण तथा मान्यता पर सवाल उठते हैं। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। मामला पिछले कई सालों से हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया गया। जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अंततः नर्सिंग छात्रों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। एडमिशन और फीस के नाम पर छात्र हर साल ठगे जा रहे हैं। समय पर परीक्षा नहीं हो रही है। किस नर्सिंग कॉलेज को मान्यता है, किसको नहीं है यह भी छात्रों को पता नहीं चल पाता है। हर स्तर पर भारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं। इसका कोई इलाज हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सरकार के पास नहीं है। हाथ में फीस की रसीद और आंखों में अपने भविष्य का सवाल लेकर छात्र यहां से वहां भटक रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है, इस पूरे विवाद की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? सरकार नहीं, नर्सिंग काउंसिल नहीं, विश्वविद्यालय नहीं और वे कॉलेज भी नहीं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। कीमत चुका रहा है, वह विद्यार्थी, जिसने नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखा था। जिन विद्यार्थियों ने 2020-21 के आसपास नर्सिंग में प्रवेश लिया, उनकी पढ़ाई सामान्य परिस्थितियों में 3 वर्षों में पूरी हो जानी चाहिए थी। पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश, मान्यता, परीक्षा, परिणाम और विश्वविद्यालय से जुड़े विवादों में फंसा हुआ है। विद्यार्थी की उम्र बढ़ गई, शिक्षा पर होने वाला खर्च बढ़ता गया। उसे यह भी नहीं मालूम कि उसकी शिक्षा कब पूरी होगी, कब वह नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। यह स्थिति केवल शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है, यह युवा पीढ़ी के साथ अन्याय है। इसके साथ ही चिकित्सा व्यवसाय में लोगों को प्रशिक्षित नर्स पिछले कई वर्षों से नहीं मिल पा रही हैं। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में तेजी के साथ बढ़ गया है। प्रशिक्षित नर्स की मांग विदेश में भी बनी हुई है। नर्सिंग के छात्र हर जगह से ठगे जा रहे हैं। उनका करियर बर्बाद हो रहा है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ में नर्सिंग से जुड़े मामले लंबे समय से सुनवाई में हैं। सीबीआई जांच तक हुई। कॉलेजों के निरीक्षण, अस्पतालों की उपलब्धता, मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल उठे। कागजों पर अस्पताल दिखाकर मान्यता लेने जैसी गड़बड़ियां हुईं, तो यह केवल किसी निजी कॉलेज की गलती नहीं मानी जा सकती। सवाल यह है, निरीक्षण करने वाली व्यवस्था ने क्या देखा? किसने रिपोर्ट दी? किसने मान्यता दी? किसने प्रवेश की अनुमति दी? अगर अस्पताल था ही नहीं, तो निरीक्षण किस आधार पर हुआ? अगर कॉलेज मानकों पर खरा नहीं उतरता था, तब विद्यार्थियों को प्रवेश क्यों मिला? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था, तो पांच साल बाद विद्यार्थी अदालतों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? विडंबना देखिए, एक ओर प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की देश और विदेश में भारी कमी बनी हुई है, अस्पतालों को प्रशिक्षित नर्सों की जरूरत है। दूसरी ओर हजारों-लाखों विद्यार्थियों का समय प्रशासनिक और कानूनी भूलभुलैया में फंस गया है। पिछले 5 साल से हाईकोर्ट में मामला होते हुए नर्सिंग के छात्र आज भी यहां से वहां भटक रहे हैं। उन्हें किसी भी स्तर पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह कैसी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें मरीज को नर्स नहीं मिलती और नर्सिंग विद्यार्थी को शिक्षा पूरी करने का अवसर नहीं मिलता? हर जगह लापरवाही और लूट देखने को मिल रही है।

सबसे गंभीर प्रश्न न्यायिक जवाबदेही का भी है। जब मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी जांच कर चुकी है। वर्षों से सुनवाई चल रही है, तब क्या केवल तारीखें ही समाधान हैं? न्याय में देरी का सबसे बड़ा नुकसान उस विद्यार्थी को होता है, जिसके जीवन के पांच वर्ष वापस नहीं आ सकते हैं। किसी विद्यार्थी के पांच वर्ष केवल कैलेंडर के पांच पन्ने नहीं होते। वे उसकी उम्र, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आर्थिक निवेश और परिवार की उम्मीदों के पांच वर्ष होते हैं। अब समय आ गया है। सरकार, नर्सिंग काउंसिल, विश्वविद्यालय और संबंधित संस्थाएं एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की राजनीति बंद करें। दोषियों पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोषी कॉलेज और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। विश्वविद्यालय दोषी हो तो उन्हें दंडित करने की कार्रवाई हो। विद्यार्थी निर्दोष हैं, उनके भविष्य की तत्काल सुरक्षा की जाए। नर्सिंग शिक्षा को भ्रष्टाचार, मान्यता और प्रशासनिक विवादों का अखाड़ा बनाना केवल विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। न्यायपालिका की विश्वसनीय और प्रभावशीलता को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी साख बनाए रखने की दिशा में काम करना होगा।

लेखक- सनत जैन

धार्मिक पर्यटन से समृद्धि और रोजगार सृजन

भारत का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उत्थान-पतन की कहानी नहीं है। यह हजारों वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक निरंतरता, आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान परंपरा, कला, स्थापत्य और सामाजिक समरसता की भी जीवंत गाथा है। मंदिर और तीर्थस्थल इस विरासत के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। वे केवल पूजा-अर्चना के स्थल नहीं, बल्कि शिक्षा, संगीत, साहित्य, लोककला, स्थापत्य और सामाजिक जीवन के केंद्र भी रहे हैं।

अमृतकाल में भारत अपनी इसी विरासत को नए आत्मविश्वास के साथ आधुनिक विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। सोमनाथ से काशी, अयोध्या से केदारनाथ और दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों तक संरक्षण, पुनर्विकास और सुविधाओं का विस्तार इसी बदलती सांस्कृतिक दृष्टि का संकेत है। इक्कीसवीं सदी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास इसी प्रक्रिया का आधुनिक उदाहरण है। दिसंबर 2021 में श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रथम चरण का उद्घाटन लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। मंदिर परिसर को गंगा तट से जोड़ने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार करने वाले इस प्रकल्प ने काशी के धार्मिक पर्यटन को नई गति दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उद्घाटन के बाद साढ़े तीन वर्षों में काशी विश्वनाथ धाम में 25.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे।

एक सरकारी आकलन के अनुसार इससे लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की जनवरी 2024 में हुई प्राण-प्रतिष्ठा ने धार्मिक पर्यटन के नए आयाम खोले हैं। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार अयोध्या धाम में पर्यटकों व श्रद्धालुओं की संख्या 2020 के लगभग 60.23 लाख से बढकर 2024 में 16.44 करोड़ हो गई है। इतनी बड़ी वृद्धि का प्रभाव होटल, परिवहन, रेस्तरां, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प, होमस्टे और अन्य सेवा क्षेत्रों पर पड़ा है। इससे स्पष्ट है कि किसी बड़े तीर्थस्थल का विकास केवल धार्मिक गतिविधि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। तीर्थस्थलों के बढ़ते विस्तार के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती है। मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में आने वाले बड़े दान का उपयोग श्रद्धालुओं के विश्वास, उनके लिए सुविधाओं के निर्माण और सार्वजनिक हित की कसौटी पर होना चाहिए। अयोध्या दान चोरी के आलोक में धन, भूमि या संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के साथ साथ दीर्घकालीन नीतियों के निर्माण की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में धार्मिक पर्यटन तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ-2025 इसका असाधारण उदाहरण रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 45 दिनों तक चले महाकुंभ में 66.30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक शक्ति के साथ-साथ विशाल स्तर पर परिवहन, स्वच्छता, आवास, सुरक्षा और डिजिटल प्रबंधन की क्षमता का भी प्रदर्शन था। केदारनाथ भी आस्था, पुनर्निर्माण और आधुनिक सुविधाओं के समन्वय का महत्वपूर्ण उदाहरण है। 2013 की विनाशकारी आपदा के बाद केदारपुरी के पुनर्विकास में सुरक्षा, मार्ग और तीर्थयात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई।

अब सोनप्रयाग-केदारनाथ 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना को 4081.28 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति मिली है, जिसकी क्षमता प्रति दिशा 1800 यात्रियों प्रति घंटे की होगी। इससे यात्रा समय को लगभग आठ-नौ घंटे से घटाकर करीब 36 मिनट करने का लक्ष्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में जलस्रोत, कचरा प्रबंधन और पारिस्थितिकी की रक्षा करना भी जरूरी हो गया है। सरकार की (पीआरएएसएचएडी) अर्थात तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। फरवरी 2025 तक पर्यटन मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 47 परियोजनाएं 1594.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत की थीं। इसके अतिरिक्त धार्मिक और विरासत स्थलों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य केवल सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि सडक, परिवहन, स्वच्छता, प्रकाश, पेयजल, आवास और अन्य आधारभूत सुविधाओं का समग्र विकास है। धार्मिक पर्यटन की अवधारणा मंदिर दर्शन से आगे बढ़ चुकी है। योग, ध्यान, आयुर्वेद, आध्यात्मिक रिट्रीट, स्थानीय खानपान, हस्तशिल्प, लोककलाएं और सांस्कृतिक उत्सव इसके नए आयाम बन रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, होमस्टे, परिवहन, डिजिटल सेवाओं और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। यदि स्थानीय समुदाय को इस अर्थव्यवस्था का वास्तविक भागीदार बनाया जाए, तो तीर्थ पर्यटन ग्रामीण और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, योग, आयुर्वेद, दर्शन, लोककलाओं और पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल माध्यमों तथा वैश्विक मंचों से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए भी इसमें बड़ी संभावनाएं हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में धार्मिक, सीमावर्ती और दूरदराज के पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 84 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें मां चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56.26 करोड़ तथा किन्नौर के रकछम और लाहौल-स्पीति के काजा में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए 24.82 करोड़ रुपए शामिल हैं। बैजनाथ, ज्वालामुखी, चामुंडा, चिंतपूर्णी, किन्नौर और कुल्लू की देव संस्कृति सहित हजारों छोटे मंदिर, मठ और लोकदेवता स्थल धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय संस्कृति और रोजगार के केंद्र बन सकते हैं। इसके लिए अनियंत्रित निर्माण के बजाय योजनाबद्ध विकास, स्वच्छता, पार्किंग, यातायात प्रबंधन, कचरा निस्तारण, भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रण किया जाना अनिवार्य है ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम हो और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देनी होगी। धार्मिक पर्यटन के लिए आस्था, पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण जरूरी है।

अनुज आचार्य, लेखक बैजनाथ से हैं

आलेख

आतंकवाद के लिए खाद पानी है नशीले द्रव्यों की तस्करी !

भारत में नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी देश की आंतरिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए एक अत्यंत गंभीर संकट बन चुकी है। भौगोलिक रूप से भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों - पश्चिम में गोल्डन क्रेसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान) और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के बीच स्थित है। इस संवेदनशील स्थिति के कारण देश में सीमा पार से बड़े पैमाने पर अवैध नशीले पदार्थों की आमद हो रही है।

नशीले पदार्थों की तस्करी में भारत की भौगोलिक स्थिति भी खासा जिम्मेदार है पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार से सटी खुली और जटिल जमीनी सीमाएं निगरानी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तस्करों द्वारा गुजरात और दक्षिणी राज्यों के विशाल तटीय क्षेत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब नशे के सौदागर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं डार्कनेट क्रिप्टो करेंसी और सीमा पार से ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का बढ़ता प्रयोग खतरा बढ़ा रहे हैं वहीं पारंपरिक अफीम-गांजे के स्थान पर हेरोइन, कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसे घातक रसायनों सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता चलन भी समस्या बन रहा है।

आपको बता दें कि देश में नशे और नशीले पदार्थों की तस्करी ने एक बार फिर केन्द्र और राज्यों की सरकारों को स्तब्ध किया है। नशीले पदार्थों की यह तस्करी का बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश पाकिस्तान के माध्यम से सीमा पार से ड्रोनों के जरिये किया जाता है। नशे को लेकर किये गये एक व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार पाकिस्तान एक प्रकार से नशीले पदार्थों के भण्डारण का केन्द्र बन गया है जहां से इन पदार्थों का बहुत बड़ा भाग भारत के पंजाब प्रांत में ड्रोनों के जरिये खपाया जाता है। भारत से फिर यह सामान तस्करी के जरिये कई अन्य देशों में भेजा जाता है जहां इसकी बड़ी मांग होती है। पाकिस्तान से भारत में पंजाब सीमा के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी यूं तो दशकों पूर्व से की जाती आ रही है। कभी नावों के माध्यम से, कभी सुरंगों के जरिये पाकिस्तानी पंजाब के सीमा-पार से भारतीय पंजाब में अफीम और हेरोइन की तस्करी की जाती रही है। तथापि, आजकल नावों का कार्य ड्रोनों से लिया जाने लगा है। ड्रोनों के जरिये पाकिस्तानी सीमा-पार से भारतीय पंजाब में अफीम, हेरोइन के साथ हथियारों की खेप भेजना जैसे आम बात हो गई है। वैसे तो नशे के लिए अफीम, चरस, कोकीन आदि अनेकानेक द्रव्यों एवं पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है किन्तु वर्तमान में हेरोइन सर्वोत्तम नशीला पदार्थ बन गया है। हाल ही में एक और बड़ा खतरनाक नशीला पदार्थ आईस भी बड़ी चर्चा

में आया है। विगत कई वर्षों से हेरोइन की तस्करी और इसके सेवन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसका बड़ा प्रमाण इस एक तथ्य से मिल जाता है कि इन दिनों सीमाओं पर विशेष सुरक्षा चौकसी होने के बावजूद तस्करी से बरामद होने वाली खेपों की संख्या और मात्रा बढ़ गई है। इसके लिए तस्करों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाने लगा है। सीमा सुरक्षा बलों की निरन्तर चौकसी और सतर्कता के बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले पांच वर्षों में पंजाब सीमा पर ड्रोन तस्करी की घटनाएं बढ़ कर तीन से 304 प्रति वर्ष तक हो गई हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में स्थितियों की गम्भीरता को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस एक कठोर टिप्पणी से बेहतर समझा जा सकता है कि नशे का यह सम्पूर्ण कारोबार महज एक आपराधिक कार्य मात्र नहीं रह गया, अपितु राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

यूं तो नशे के सेवन और नशीले पदार्थों की तस्करी से गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रदेश बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं किन्तु पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। प्रदेश के युवाओं में नशे की समस्या एक गम्भीर संकट के रूप में उभर रही है। पंजाब सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत प्रदेश का पुलिस तंत्र युवाओं को इस महारोग से बचाने के लिए भरसक यत्न कर रहा है किन्तु यह समस्या एक ऐसे बिगड़ैल घोड़े के समान हो गई है कि जिसकी नाक में आसानी से नकेल नहीं डाली जा सकती।

अभी हाल में अमृतसर के थाना लोपोके क्षेत्र में सीमा पार से आई लगभग 180 करोड़ रुपये की 19 किलो हेरोइन के साथ महिला सहित तीन तस्करों को हिरासत में लिया गया। नशा तस्करी में यह भी एक नई प्रवृत्ति सामने आई है कि अवयस्क बालकों को थोड़े से लालच के वशीभूत इस गैर-कानूनी कार्य में शामिल किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों की शमूलियत से इस अवैध क्रिया-कलाप को एक नया मोड़ मिला है। पिछले कुछ समय में पंजाब में पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े कई अवयस्कों और महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। प्रदेश सरकार ने अपने ऑपरेशन प्रहार के दौरान लगभग 4000 तस्करों-गैंगस्टरों को गिरफ्तार भी किया है। इतने बड़े स्तर पर तस्करों की गिरफ्तारी, इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेपों की बरामदगी से तस्करी पर काबू पाये जाने की सम्भावना बनती है, किन्तु इतनी बड़ी बरामदगी और बड़े स्तर पर युवाओं और अव्यवस्कों की भागीदारी से इस कारोबार की भीषणता भी जाहिर होती है। पंजाब सरकार के प्रहार अभियानों और प्रदेश के पुलिस तंत्र की सक्रियता से बेशक प्रदेश के लोगों के मन में आशा और विश्वास की एक लकीर उपजते दिखाई देती है, किन्तु हम समझते हैं कि लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाना भी बहुत जरूरी है। पुलिस तंत्र की सक्रियता कागजों में भी हो, किन्तु धरातल पर उसे दिखाई भी अवश्य देना चाहिए। कानून के हाथ लम्बे होते हैं, किन्तु ये हाथ अपराधियों और तस्करों के गिरेबान तक पहुंचने भी तो चाहिएं। कुछ भी हो अथवा कुछ भी किया जाए, देश को नशीले पदार्थों की तस्करी की इस लानत से मुक्ति मिलनी चाहिए।

देश की कामकाजी आबादी खासकर युवा और कालेज छात्र छात्राएं स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आकर मानसिक और शारीरिक रूप से पंगु हो रहे हैं।नारको-टेररिज्म जड़ जमा रहा है। ड्रग्स की तस्करी से होने वाली अवैध कमाई का इस्तेमाल सीधे तौर पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों और उग्रवाद की फंडिंग में किया जाता है। नशे की दैनिक तलब पूरी करने के लिए युवा चोरी, लूटपाट और संगठित अपराधों के रास्ते पर जा रहे हैं। अवैध काले धन और हवाला कारोबार के कारण देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है।

ऐसा नहीं है कि सरकार को नशीले द्रव्यों की तस्करी और उसके कारण हो रही बबार्दी का भान नहीं है सरकार ने इस ओर नियंत्रण के लिए की प्रभावी कदम उठाए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 - 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से 1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तस्करी की गुप्त सूचनाएं दे सकते हैं। तस्करों की संपत्तियों को कुर्क करने और पीआइटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत आदतन अपराधियों को बिना जमानत जेल में रखने की कार्रवाई तेज कर दी गई है अभी और अधिक असरदार कारवाई और सख्ती की जरूरत है।

लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

जामिया के 26 छात्रों का प्लेसमेंट, 18 लाख रुपये तक का पैकेज

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 26 छात्रों का विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। इनमें बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के चार छात्रों का चयन 18 लाख रुपये सालाना सीटीसी पैकेज पर हुआ है। वहीं, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एमसीए के 22 छात्रों का भी चयन हुआ है।विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल के अनुसार, चार छात्रों के चयन के लिए पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया गया था। इसमें ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के तीन दौर के बाद छात्रों का अंतिम चयन किया गया।वहीं, 22 छात्रों के चयन के लिए इस महीने की शुरूआत में जामिया के यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया गया।

मुखर्जी नगर इलाके में दो शव मिलने से सनसनी

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में गुरुवार को अलग-अलग स्थानों पर दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहला शव दशहरा ग्राउंड में बारिश के पानी से भरे गड्ढे से बरामद हुआ, जबकि दूसरा हकीकत नगर के पास रिंग रोड के फुटपाथ पर मिला। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। दशहरा ग्राउंड में गहरे गड्ढे में एक युवक का शव तैरता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम टीम को शव पर चोट के निशान नहीं मिले। मृतक की पहचान 35 वर्षीय दीपक के रूप में हुई। शुरूआती जांच में पता चला कि वह शराब के नशे में नहाने के लिए पानी से भरे गड्ढे में उतरा था। गहराई का अंदाजा नहीं होने से वह डूब गया।

परिजनों ने भी किसी तरह का संदेह नहीं जताया है। वहीं, हकीकत नगर के पास फुटपाथ पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के एक अज्ञात शख्स का शव मिला। पास से मिले थैले में कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस इनके जरिए मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

रक्षाबंधन सड़कों पर यातायात रहेगा प्रभावित

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। रक्षाबंधन के अवसर पर शुक्रवार को विकास मार्ग, आनंद विहार बस अड्डा, रोड संख्या 56 और एनएच-9 पर राहगीरों एवं वाहन चालकों की संख्या ज्यादा रहने की संभावना है। इस भीड़भाड़ के चलते ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इन मार्गों से दूर रहने एवं वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताए गए रास्तों से जाने की सलाह दी है।

20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। द्वारका जिला अदालत ने 20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी मोहिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी अपने बचाव में विश्वसनीय और सुसंगत कहानी पेश करने में विफल रहा। साथ ही वह यह भी साबित नहीं कर सका कि विवादित चेक का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नितेश गोयल की अदालत संजय कुमार की ओर से दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही थी।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच वर्षों से पारिवारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मार्च 2013 में आरोपी ने आर्थिक जरूरत बताते हुए 20 लाख रुपये का दोस्ताना ऋण लिया था और बदले में द्वारका स्थित एक दुकान के मूल दस्तावेज सुरक्षा के तौर पर दिए थे। बाद में ऋण चुकाने के लिए आरोपी ने 20 लाख रुपये का चेक जारी किया।

पुरानी दिल्ली छह की शानदार जीत

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के एलिमिनेटर मुकाबले में पुरानी दिल्ली छह ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को सात विकेट से हराकर क्वालीफायर-2 में प्रवेश कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आउटर दिल्ली वॉरियर्स 19.4 ओवर में 179 रन पर ऑलआउट हो गई। प्रियांश आर्य ने 32 गेंदों पर 57 रन, जबकि अक्षय सैनी ने 26 गेंदों पर 42 रन बनाए। पुरानी दिल्ली की ओर से राजनेश दादर ने तीन, उदव मोहन व देव लाकड़ा ने दो-दो विकेट लिए। 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 ने पांच रन पर समर्थ सेठ का विकेट गंवा दिया। इसके बाद आर्यन गौर 23 गेंद में 36 रन और देव लाकड़ा 32 गेंद में 82 रन ने 67 रन की साझेदारी की।

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और राजस्थान डिप्टी सीएम दीया कुमारी सहित कई नेताओं ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बच्चों के बीच त्योहारों की खुशी कुछ और ही होती है। आज दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आए मेरे प्यारे लिटिल फ्रेंड्स के साथ रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने आगे लिखा, ह्यइन्होंने बहुत प्यार से बहुत सारी राखियां बांधीं, जमकर मिठाई खिलाई और फिर शुरू हुई अनलिमिटेड बातें, हंसी और ढेर सारी शरारतें। मेरे बच्चों, तुम्हारा यह प्यार मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। तुम्हारी मुस्कान हमेशा यूं ही खिलती रहे, तुम्हारे सपनों को हर अवसर मिले और दिल्ली तुम्हारे लिए हमेशा सुरक्षित और संभावनाओं से भरी रहे। आज कलाई पर बहुत सारी राखियां हैं और दिल में तुम सबका ढेर सारा प्यार।

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजीत कुमार और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को राखी बांधी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजीत कुमार एवं राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की मंगलकामना की। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें तथा संगठन और राष्ट्रसेवा के पथ पर निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते रहें।

हरियाणा भाजपा अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने लिखा, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम मेहर मलिक, राम भतेरी एवं ऋषिपाल रावल तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष, मतलौडा सोमबीर मलिक को रक्षासूत्र बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि एवं दीघार्यु की मंगलकामना की। भाई-बहन के स्नेह और विश्वास का यह पावन पर्व सभी के जीवन में खुशियां एवं नई ऊर्जा लेकर आए। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज पटना स्थित आवास पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्माकुमारी स्नेहा बहन एवं बी.के. सावित्री माता ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राखी बांधी। बहनों से मिले स्नेह एवं शुभाशीष के लिए हृदय से आभार।

21 वर्षीय की छात्रा की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या से सनसनी

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में एक 21 वर्षीय की छात्रा और मॉडल की कथित तौर पर उसके घर के अंदर चाकू मारकर हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस को शक है कि वारदात में उसके जिम ट्रेनर का हाथ हो सकता है।

मृतक महिला की पहचान मुस्कान के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को जब कथित हमला हुआ, तब वह दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में अकेली थी। आरोपी, जिसकी पहचान इमरान के तौर पर हुई है, कथित तौर पर घर में घुसा, चाकू से उस पर हमला किया और मौके से भाग गया।

मदद के लिए मुस्कान की चीखें सुनकर पड़ोसी उसके घर पहुंचे और उसे गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ हालत में पाया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने पत्रकारों को बताया, हम आरोपी की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आस-पास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है।

मुस्कान के दोस्त अमन ने बताया कि वह तीन बहनों में सबसे छोटी थी। उनके अनुसार, उसकी एक बड़ी बहन, जो अभी चंडीगढ़ में है, ने उन्हें फोन किया और हमले के बारे में पता चलने पर मुस्कान के घर तुरंत पहुंचने को कहा। मृतक महिला के एक दोस्त ने बताया, मुझे एक कॉल आया था, लेकिन मुझे सही समय याद नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि वे घर पर नहीं हैं और कोई घर में घुसकर मुस्कान को चाकू मार गया है।

दोस्त ने बताया कि कथित हमलावर की पहचान इमरान के तौर पर हुई है, जो उसी जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करता था जहां मुस्कान जिम करती थी। अमन ने कहा कि उन्होंने तुरंत एक और दोस्त से संपर्क किया और उसे घर पहुंचने और यह पक्का करने के लिए कहा कि मुस्कान को अस्पताल ले जाया जाए। जब तक वह वहां पहुंचा, एम्बुलेंस पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी और उसे इलाज के लिए ले जा चुकी थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुस्कान की बहनों ने पहले भी इमरान की ओर से उसे परेशान करने को लेकर चिंता जताई थी। अमन ने कहा, ह्यउसने पहले भी उसे परेशान किया था, और इस घटना के बाद तुरंत उस पर शक गया।

दंगों के मास्टरमाइंड थे शरजील और उमर खालिद

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को मास्टरमाइंड बताया है। अदालत में पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं का भी विरोध किया। 31 जुलाई को पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने को कहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा, शरजील इमाम और उमर खालिद दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे। पुलिस के पास इनके खिलाफ दंगों की योजना बनाने, लोगों को जुटाने और दंगों में रणनीतिक भूमिका निभाने से जुड़े अहम सबूत है।

इस कठिन समय में भारत नेपाल के साथ पूरी तरह से खड़ा है: दिल्ली की मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत इस कठिन समय में पड़ोसी देश के साथ खड़ा है। गुप्ता ने कहा कि नेपाल में एक दर्दनाक त्रासदी हुई है और उसे हर संभव मदद दी जाएगी।

गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा, इस कठिन समय में भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। देश में एक दर्दनाक त्रासदी हुई है, नेपाल को हर संभव मदद दी जाएगी। मैं नेपाल के सभी निवासियों की सुरक्षा और राहत के लिए प्रार्थना करती हूं।

उन्होंने कहा, मैं भगवान पशुपतिनाथ से भी प्रार्थना करती हूं कि नेपाल को दुख की इस घड़ी से उबरने की शक्ति दें और वहां के सभी नागरिक सुरक्षित रहें और उन्हें जल्द राहत मिले। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ बातचीत कर रही है क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जिनके रिश्तेदार नेपाल गए होंगे। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है।

बुधवार को आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के तीन जिलों में भारी तबाही मचाई। इस विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 270 हो गई। नेपाल पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि अधिकारी लापता हजारों लोगों की तलाश में युद्धस्तर पर जुटे हैं। लापता लोगों में 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं।

आईआईटी दिल्ली में प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। आईआईटी दिल्ली में एमएससी भौतिकी के छात्र की मौत के मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने परिसर में सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और प्रदर्शन के वीडियो बनाने पर छात्र भड़क गए और उन्होंने इस बारे में सवाल उठाए। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन का रवैया छात्र हितैषी नहीं है। इस बीच संस्थान ने मामले की जांच के लिए बाहरी समिति का पुनर्गठन करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता को अध्यक्ष बनाया है। बुधवार रात निदेशक की ओर से छात्रों को भेजे ई-मेल के अनुसार समिति में एम्स, नई दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रताप शर्मा, दो छात्र प्रतिनिधि और आईआईटी दिल्ली के रजिस्ट्रार भी शामिल हैं। इससे पहले समिति के अध्यक्ष बनाए गए उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने खुद को अलग कर लिया था। छात्र भौतिकी विभाग की विभागाध्यक्ष और छात्र कल्याण से जुड़े अधिकारियों के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी से बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सादी वर्दी में पुलिस की मौजूदगी और पहचान पत्र दिखाने को लेकर बातचीत होती दिख रही है।

सादी वर्दी में पुलिस की मौजूदगी पर भड़के छात्र

आईआईटी दिल्ली ने कहा कि हर छात्र उसके लिए महत्वपूर्ण है और छात्र कल्याण उसकी प्राथमिकता है। संस्थान ने शैक्षणिक दबाव कम करने, मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और शिकायत निवारण की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। 2025 में नया पाठ्यक्रम लागू होने के बाद प्रथम सेमेस्टर का क्रेडिट भार कम किया गया, जीवन कौशल के पाठ्यक्रम जोड़े गए और प्रथम वर्ष की विभागीय कक्षाओं में छात्रों की संख्या 30 से 60 तक सीमित की गई। सप्ताहांत की परीक्षाएं कम की गईं और क्रेडिट वितरण में लचीलापन रखा गया। 2024-25 से बीटेक के लिए न्यूनतम सीजीपीए की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई। स्टूडेंट-टीचर इंटरैक्शन काउंसिल के माध्यम से नियमित बैठकें, शिक्षकों के खुले संवाद का समय, परियोजना मार्गदर्शन, छात्रावास स्तर पर सहभागिता और कक्षा समितियों के माध्यम से छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। संस्थान के अनुसार 24 घंटे परामर्शदाता और मनोचिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें एम्स और विमहांस के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। बाहरी मानसिक स्वास्थ्य उपचार का पूरा खर्च लौटाने और आपात स्थिति में त्वरित सहायता की व्यवस्था है।

ज्वेलरी चुराकर भागने वाला नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। पंजाबी बाग एक्सटेंशन इलाके में घरेलू सहायक की नौकरी पर आए युवक ने मौका मिलते ही घर से करीब 60 लाख रुपये के आभूषण चोरी कर लिए और दिल्ली से फरार हो गया। चोरी की ज्वेलरी लेकर वह नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन पंजाबी बाग थाना पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए उसे बिहार में नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय शशिकांत के रूप में हुई है। उसके पास से चोरी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि 21 अगस्त को एक दिन पहले ही शशिकांत को घरेलू सहायक के तौर पर रखा था।

अदालत ने पुरानी मोटरसाइकिल को कबाड़ में बदलने के मामले में मुआवजे की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्धारित उपयोग अवधि पूरी कर चुकी मोटरसाइकिल को कथित तौर पर अनुचित तरीके से जब्त कर कबाड़ में बदलने के लिए शहर के प्रशासन को एक करोड़ रुपये से अधिक मुआवजे का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने एकल न्यायाधीश के राहत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली वाहन मालिक की अपील को खारिज कर दिया। परिवहन अधिकारियों ने दिसंबर 2024 में सार्वजनिक सड़क से 18 साल पुरानी मोटरसाइकिल को यह कहते हुए जब्त कर लिया था कि यह अपनी निर्धारित उपयोग की अवधि पूरी कर चुके वाहन (ईएलवी) की श्रेणी में आती है। इसके बाद मोटरसाइकिल को कबाड़ में बदल दिया गया।

अपीलकर्ता ने दलील दी कि मोटरसाइकिल उसके आवास के बाहर खड़ी थी और पिछले चार साल से इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण प्रदूषण नहीं फैला रही थी। अपीलकर्ता ने दावा किया कि मोटरसाइकिल को उचित नोटिस दिए बिना ही कबाड़ में बदल दिया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन है।

संविधान के अनुच्छेद 300ए में निहित है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता ने वाहन की अनुचित जब्ती और उसे कबाड़ में तब्दील किए जाने के कारण मानसिक पीड़ा, लंबे समय तक प्रयास एवं उत्पीड़न के लिए अधिकारियों से 1.43 करोड़ रुपये मुआवजे का अनुरोध किया था।

अपीलकर्ता ने कहा कि इस मोटरसाइकिल से उसका भावनात्मक जुड़ाव था। अपीलकर्ता ने कथित तौर पर अधिक मूल्य वाले, अच्छी तरह रखरखाव किए गए और पुरातन निजी वाहन को नष्ट करने के साथ-साथ मानहानि के लिए भी हजार्ने का अनुरोध किया। वहीं, अधिकारियों ने अदालत को बताया कि मोटरसाइकिल को वाहन कबाड़ सुविधा के पंजीकरण एवं कार्य संबंधी नियम, 2021 के तहत कबाड़ में बदला गया था, क्योंकि वाहन मालिक तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक घोषणा-पत्र दाखिल करने में विफल रहा था। खंडपीठ ने 24 अगस्त को दिए गए अपने फैसले में एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए दीवानी अदालत में वाद दायर करने को कहा था।

आईआईटी दिल्ली ने कहा हर छात्र महत्वपूर्ण, छात्र कल्याण प्राथमिकता

नई दिल्ली, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। आईआईटी दिल्ली में एक छात्र की आत्महत्या के मामले के बाद संस्थान ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारे लिए हर छात्र महत्वपूर्ण है और हमारी कोशिश होती है कि किसी भी छात्र को किसी तरह की परेशानी न हो। संस्थान हर संभव हर छात्र के लिए बेहतरी का प्रयास करता है।

गुरुवार को जारी जानकारी में संस्थान आईआईटी दिल्ली ने कहा कि छात्रों का कल्याण उसकी प्राथमिकता है और परिसर में ऐसा माहौल बनाने के लिए कई व्यवस्थाएं पहले से लागू हैं, जहां हर छात्र की बात सुनी जाए और उसे जरूरी सहयोग मिल सके। संस्थान ने शैक्षणिक राहत, मेंटरशिप, मानसिक स्वास्थ्य, शिकायत निवारण, विविधता और लक्षित सहायता से जुड़े उपायों को अलग-अलग बताया है। आईआईटी दिल्ली ने बताया कि 2025 में नया पाठ्यक्रम लागू होने के बाद प्रथम सेमेस्टर के क्रेडिट लोड को कम किया गया है। जीवन कौशल से जुड़े पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं और प्रथम वर्ष की विभागीय कक्षाओं में छात्रों की संख्या 30 से 60 के बीच सीमित की गई है। संस्थान के अनुसार इसका उद्देश्य छात्रों पर शैक्षणिक दबाव कम करना है। सप्ताहांत में होने वाली परीक्षाओं को भी कम किया गया है और क्रेडिट वितरण में लचीलापन रखा गया है। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से बीटेक की डिग्री के लिए न्यूनतम सीजीपीए की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

संस्थान ने बताया कि स्टूडेंट-टीचर इंटरैक्शन काउंसिल के माध्यम से प्रत्येक सेमेस्टर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। शिक्षक छात्रों से ओपन-डोर ऑफिस आवर्स के जरिए संवाद करते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मार्गदर्शन, हॉस्टल स्तर पर सहभागिता और क्लास कमेटी के फीडबैक के जरिए छात्रों की समस्याओं और सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। आईआईटी दिल्ली के अनुसार छात्रों के लिए 24 घंटे काउंसलर और मनोचिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें एम्स और विमहांस के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। संस्थान ने बाहरी मानसिक स्वास्थ्य उपचार के खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति की व्यवस्था और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल होने की बात कही है। अकादमिक यूनिट वेलनेस कमेटियां भी छात्रों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं।

आईआईटी दिल्ली ने छात्र साथी कार्यक्रम का भी विस्तार किया है। पहले यह सुविधा स्नातक छात्रों के लिए थी। 2025 में इसे परास्नातक और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी शुरू किया गया, ताकि उन्हें पढ़ाई और कैंपस जीवन से जुड़ी चुनौतियों में सहयोग और मार्गदर्शन मिल सके। संस्थान ने बताया कि पहले स्नातक छात्रों को सहयोग और मेंटरशिप दी जाती है। वर्ष 2025 में इसका विस्तार करते हुए पीजी बडी और इंटरनेशनल बडी प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन इन इंजीनियरिंग के माध्यम से योग और ध्यान जैसे मॉड्यूल लंबे समय से चलाए जा रहे हैं।

विकसित भारत को आकार देने के लिए तैयार हो रही हैं छात्राएं : उपराज्यपाल

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि छात्राएं केवल भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी नहीं कर रही हैं, बल्कि भविष्य के भारत को आकार देने की तैयारी कर रही हैं। उनकी पीढ़ी के पास ऐसी तकनीक विकसित करने और उसे नई दिशा देने का अवसर है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, विनिर्माण, शासन और दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बदलाव ला सकती है। इसलिए छात्राओं को केवल तकनीक का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि तकनीक की निमार्ता और नवोन्मेषक बनकर देश के भविष्य को नई दिशा देनी चाहिए।

आईजीडीटीयूडब्ल्यू में प्रवेश कार्यक्रम

उपराज्यपाल गुरुवार को इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय महिला (आईजीडीटीयूडब्ल्यू) में आयोजित प्रबोधन प्रवेश कार्यक्रम-2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान विश्वविद्यालय के आधुनिक व्याख्यान कक्ष परिसर का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज बेटियां इंजीनियरिंग, तकनीक, विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा समेत हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक, ज्ञान और अनुभव का कोई जेंडर नहीं होता। उन्होंने छात्राओं से

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों की निमार्ता बनकर भविष्य के समाधान तैयार करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्राओं को जिज्ञासा, साहस और चरित्र को अपनी ताकत बनाना चाहिए और केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बनने का प्रयास करना चाहिए।

शिक्षा मंत्री की बातें

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि तेजी से बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप छात्राओं को तैयार करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने तकनीक, कौशल, नवाचार और व्यावहारिक सीखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने छात्राओं की ओर से दिल्ली पुलिस के लिए विकसित निगरानी ड्रोन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह तकनीक को समाज की वास्तविक जरूरतों के समाधान में बदलने की क्षमता का उदाहरण है। उन्होंने छात्राओं से महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और हरित तकनीक के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने का आह्वान किया।

दिल्ली सरकार की योजनाएँ

शिक्षा मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार करीब 160 एकड़ में शिक्षा नगरी विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। विद्यार्थियों और युवा उद्यमियों को सहयोग देने के लिए 400 करोड़ रुपये की स्टार्टअप और नवोन्मेष केंद्र नीति को मंजूरी दी गई है।

संक्षिप्त वार्ता

रुद्रा बुद्धा एन्क्लेव रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी के हरियाली तीज आयोजन में सरोज सिंह बनी तीज क्वीन

वेब वार्ता, वाराणसी। सारनाथ स्थित रेड पैलेस में रुद्रा बुद्धा एन्क्लेव सोसायटी की अध्यक्ष कल्पना तिवारी की अध्यक्षता में हरियाली तीज का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में सरोज सिंह को उनके सुंदर सोलह श्रृंगार और पारंपरिक तीज श्रृंगार के लिए तीज क्वीन चुना गया। उन्होंने पूरे सोलह श्रृंगार के साथ सभी का मन मोह लिया। सोसायटी अध्यक्ष कल्पना तिवारी ने बालों में सुंदर गजरा सजाकर महिलाओं का स्वागत किया। जिससे कार्यक्रम में तीज की पारंपरिक खुशबू और उत्सव का रंग और भी गहरा हो गया। आयोजन में महिलाओं के लिए विविध प्रकार के सरप्राइज गेम्स, मनोरंजक खेल एवं सोलह श्रृंगार गेम आयोजित किए गए। इन खेलों में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की और कार्यक्रम को खूब आनंदमय बनाया।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति किया जागरूक

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। मिशन शक्ति अभियान फेज-5 .0 के द्वितीय चरण के तहत गुरुवार को थाना संडीला की मिशन शक्ति टीम ने बस अड्डा संडीला पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। इस दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के साथ सरकार द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। टीम ने महिलाओं को 112, 1090, 181, 1076, 1098, 108, 102, 101 और 1930 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया। साथ ही साइबर अपराध एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय समझाते हुए साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करने की जानकारी दी गई।

अभियान के दौरान महिला उपनिरीक्षक मीनाक्षी राणा, महिला आरक्षी प्रियंका राजपूत एवं महिला आरक्षी वैशाली मौजूद रहीं।

डीजीपी मुख्यालय में बच्चों के साथ मनाया गया रक्षाबंधन

लखनऊ। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर डीजीपी मुख्यालय में आज भावनात्मक और आत्मीय माहौल देखने को मिला। डीजीपी राजीव कृष्ण ने जनभवन के मॉडर्न विद्यालय के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस अवसर पर राजीव कृष्ण ने राजकीय बाल गृह की अनाथ एवं निराश्रित बच्चियों से रक्षा सूत्र बंधवाया और उन्हें स्नेह एवं आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ डीजीपी ने आत्मीय संवाद भी किया और रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में साइबर क्राइम/112/CID IPS बीके सिंह भी मौजूद रहे। डीजीपी मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम ने रक्षाबंधन के पर्व को भाई-बहन के स्नेह के साथ-साथ सामाजिक सरोकार और संवेदनशीलता का संदेश भी दिया।

शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। कुल 55 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और फरियादियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान कराया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

छात्राओं की रचनात्मकता देख गदगद हुए अधिकारी

वेब वार्ता,लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। भाई-बहन के पवित्र प्रेम और स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) कछौना की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को अपने हाथों से तैयार की गईं सुंदर एवं आकर्षक राखियां बांधीं। छात्राओं के इस स्नेहपूर्ण और आत्मीय प्रयास ने रक्षाबंधन के पर्व की खुशियों को और भी खास बना दिया। विद्यालय की वार्डन पूनम अवस्थी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचीं छात्राओं ने जिलाधिकारी अनुनय झा तथा मुख्य विकास अधिकारी को पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ रक्षा सूत्र बांधा। छात्राओं ने अधिकारियों की कलाई पर राखी सजाते हुए उनकी दीघार्यु, सुख-समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान रक्षाबंधन के पारंपरिक भाव के साथ ही छात्राओं और अधिकारियों के बीच भाई-बहन जैसा स्नेहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। विद्यालय की छात्राओं ने इस अवसर के लिए बाजार से राखियां खरीदने के बजाय अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय देते हुए स्वयं आकर्षक राखियां तैयार की थीं।

जीआरपी पुलिस ने यात्रियों को लौटाए 611 गुमशुदा मोबाइल फोन

611 मोबाइल फोन की कीमत दो करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक

वेब वार्ता, कानपुर। रक्षाबन्धन महापर्व पर यात्रा के दौरान गुम हुए मोबाइल को जीआरपी पुलिस ने यात्रियो को लौटाया तो उनके चेहरे खुशी से खिले उठे। थाना प्रभारी जीआरपी ओम नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग प्रयागराज प्रशान्त कुमार वर्मा द्वारा इस प्रशंसनीय कार्य के लिए पूरी टीम को दस हजार रु0 पुरस्कार की घोषणा की।

पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी0 द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल ओम नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आपरेशन मुस्कान के तहत गठित टीम द्वारा विभिन्न कम्पनियों के छः सौ ग्यारह (611) गुमशुदा मोबाइल को जीआरपी सर्विलांस सेल की मदद से बरामद किये गये है। पुलिस अधीक्षक रेलवे, प्रयागराज प्रशान्त कुमार वर्मा द्वारा मोबाईल वितरण समारोह में बरामद मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियो को विधिवत सुपुर्द किए गए। मोबाइल प्राप्त करने वाले यात्रियो के चेहरे खुशी से खिल उठे।

मोबाइल लौटाए जाने के दौरान, उपस्थित यात्रियो ने थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कार्य जीआरपी पुलिस की सतर्कता, प्रतिबध्दता और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। इस पहल से न केवल यात्रियो का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हुआ है, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ है कि जीआरपी पुलिस हर पीड़ित की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। कुल बरामद मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक है।

पकडने पवाली टीम

गुमशुदा मोबाइल फोन को बरामद करने वाली टीम में प्रमुख रूप से एसआई विनोद कुमार यादव, धीरेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी चौकी जीआरपी गोबिन्दपुरी, मोहित कुमार, सुनील कुमार, मनोज कुमार, अजीत प्रताप, शशिकान्त सरोज, अरबिन्द गुप्ता, नीरज कुशवाहा, शिवबाबू यादव व राधा मोहन द्विवेदी,हे0कां०मिथिलेश,शिवप्रताप सिंह,शिव सिंह, शिव प्रकाश सर्विलाशं सेल अनुभाग प्रयागराज, राज कमल वर्मा, सतेन्द्र सिंह समेत अन्य पुलिस कर्मी थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल रहे।

यूपी की आबादी चुनौती नहीं, बड़ी संभावना: मुख्यमंत्री

वेब वार्ता, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली, ऊजार्वान युवा वर्कफोर्स यूपी में है। इन्हें प्लेटफॉर्म उलब्ध कराना सरकार का काम है। राजदूत, उच्चायुक्त समेत विदेशी प्रतिनिधिमंडल मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से अधिक है, इसलिए आपके सामने बड़ी चुनौती है। मैं उनसे कहता हूं कि जितनी बड़ी चुनौती, उतनी ही बड़ी संभावना है। यूपी की जिस आबादी को लोग चुनौती कहते हैं, हम उसे डेमोग्रॉफिक डेविडेंड मानते हैं। इनके स्केल को स्किलिंग से जोड़कर इसका उपयोग डेमोग्रॉफिक डेविडेंड के रूप में कर पाते हैं।

मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को 3 .42 करोड़ रुपये से अधिक और 9 इनक्यूबेटर्स को 1 .79 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण करने के उपरांत युवा उद्यमियों व उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 पुस्तिका का विमोचन तथा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस दौरान लघु फिल्म के माध्यम से यूपी के स्टार्टअप इकोसिस्टम से अवगत कराया गया। सीएम योगी ने 2014 से पहले और इसके बाद भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत में व्यापक बदलाव दिख रहा है। 2014 के पहले देश में मात्र 500 स्टार्टअप्स थे, अब इनकी संख्या ढाई लाख से ऊपर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अब भारत के युवाओं के सपनों की उड़ान को गति दे रहा है। 2017 से पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी थी।

मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विकास में सहभागी उद्यमियों का किया सम्मान

वेब वार्ता, लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास में सहभागी उद्यमियों का मंच पर सम्मान किया। उन्होंने भारत इनोवेट्स में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया। उन्होंने स्टार्टअप प्रोत्साहन, इन्क्यूबेटर्स प्रोत्साहन राशि के चेक का वितरण किया। साथ ही इन्क्यूबेटर मान्यता प्रमाण पत्र व यूपी स्टार्टअप फंड समर्थित स्टार्टअप्स का भी सम्मान किया।

मुख्यमंत्री ने मंच पर 5 स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि के चेक का वितरण किया। उन्होंने सिंह डायनमिक प्रा. लि. की अनुषी वर्मा, डिकोड सॉफ्टवेयर्स प्रा. लि. की रिया कुमारी वंशगोपाल, त्रिशूल स्पेस के दिव्यम, जीनोमिकी सॉल्यूशन प्रा. लि. की डॉ. दीक्षा भारती व पीएचएसआई टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रा. लि. के तुषार राज को सम्मानित किया। सीएम ने इन्क्यूबेटर्स प्रोत्साहन राशि के चेक का भी वितरण किया। इसके अंतर्गत उन्होंने नवयुग नवाचार फाउंडेशन, आईईटी लखनऊ के डॉ. पुष्कर व एनआईईटी के डॉ. संजय कुमार को सम्मानित किया।

इफको एमसी के 12वें स्थापना दिवस पर हुई किसान गोष्ठी, नैनो उत्पादों की दी गयी जानकारी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। इफको किसान सेवा केंद्र शाहाबाद में इफको एमसी के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल पोषण तथा इफको एमसी के विभिन्न कृषि उत्पादों के उपयोग और महत्व की जानकारी दी गई। किसानों को वैज्ञानिक एवं संतुलित तरीके से खेती अपनाकर बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया।

केंद्र प्रभारी अमित कुमार झा ने किसानों को इफको एमसी के नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो जिंक एवं नैनो कॉपर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नैनो उत्पादों की उपयोग विधि, उचित मात्रा तथा फसल के विभिन्न चरणों में इनके प्रयोग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फसल की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग पौधों की वृद्धि, विकास और गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है।

गोष्ठी में किसानों ने नैनो उत्पादों के प्रयोग, मात्रा, छिड़काव की विधि तथा विभिन्न फसलों में इनके उपयोग को लेकर सवाल किए। केंद्र प्रभारी ने किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उत्पादों के सही एवं वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से कृषि विशेषज्ञों की सलाह और अनुशंसित मात्रा के अनुसार ही उर्वरकों व पोषक तत्वों का प्रयोग करने की अपील की। इस दौरान संतुलित उर्वरक उपयोग, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता तथा आधुनिक कृषि तकनीकों पर भी चर्चा हुई। किसानों ने गोष्ठी में मिली कृषि संबंधी जानकारी को उपयोगी बताया। अमित कुमार झा ने कहा कि किसानों तक उन्नत कृषि तकनीक और उत्पादों की सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है, जिससे वे फसल की आवश्यकता के अनुसार उचित निर्णय लेकर उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार कर सकें।

बलरामपुर की चारों दिशाओं में बनेंगे भव्य स्वागत द्वार, नगर की पहचान को मिलेगा नया स्वरूप

बलरामपुर/कमर खान

आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर की सीमाओं को आकर्षक एवं भव्य स्वरूप प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ.धीरेन्द्र प्रताप सिंह ह्यधीरूह्न ने बुधवार को नगर की चारों दिशाओं में स्थित नगर सीमाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित भव्य एवं आकर्षक स्वागत द्वारों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थलों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अध्यक्ष डॉ.धीरेन्द्र प्रताप सिंह ह्यधीरूह्न ने कहा कि नगर की सीमाओं पर निर्मित होने वाले स्वागत द्वार केवल नगर की सीमा को चिह्नित करने तक सीमित नहीं रहेंगे,बल्कि ये बलरामपुर की गौरवशाली पहचान,सांस्कृतिक विरासत,ऐतिहासिक परंपरा और विकास की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनेंगे। उन्होंने कहा कि नगर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में बलरामपुर की विशिष्ट पहचान और समृद्ध परंपरा की एक सुंदर एवं सशक्त छवि अंकित हो,इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वागत द्वारों की परिकल्पना की जा रही है।

उन्होंने कहा कि स्वागत द्वारों को आधुनिक,आकर्षक और भव्य स्वरूप दिए जाने के साथ ही इनके निर्माण में नगर की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान को भी प्रमुखता दी जाएगी। इससे नगर के प्रमुख प्रवेश मार्गों की सुंदरता बढ़ेगी और बलरामपुर की एक विशिष्ट पहचान स्थापित होगी।

नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बलरामपुर को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित और भव्य स्वरूप प्रदान करना नगर पालिका की प्राथमिकता और संकल्प है। नगर के सौंदर्यीकरण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकास की यह यात्रा आगे भी निरंतर जारी रहेगी और बलरामपुर नई पहचान के साथ नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थलों की स्थिति,उपलब्ध स्थान,यातायात व्यवस्था तथा निर्माण की संभावनाओं का भी जायजा लिया। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्तावित कार्य को बेहतर एवं आकर्षक स्वरूप में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

आईटीआई प्रथम प्रवेश सूची में चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू

वेबवार्ता। हरदोई। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हरदोई आरके श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में संचालित समस्त राजकीय, निजी एवं पीपीपी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश सत्र 2026 की प्रथम सूची में चयनित अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची संस्थानों को प्राप्त हो गई है। निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया 27 अगस्त से 4 सितंबर 2026 की शाम पांच बजे तक, अवकाश सहित, संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम सूची में चयनित अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में अपने संबंधित चयनित संस्थान में प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को समस्त मूल प्रमाण-पत्र, अंकपत्र एवं उनकी एक-एक प्रमाणित प्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा एससीवीटी पोर्टल से प्राप्त बुलावा पत्र साथ लाना होगा।

नेपाल में बादल फटने से उफान पर नदियां, कुशीनगर में बाढ़ का खतरा

वेब वार्ता, कुशीनगर

नेपाल के त्रिशूली और भोटेकोशी नदी क्षेत्रों में भारी बारिश व बादल फटने से आई भीषण आपदा का असर अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों पर दिखने लगा है। त्रिशूली नदी में आए उफान और जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के चलते भारतीय निचले इलाकों में बाढ़ की गंभीर आशंका पैदा हो गई है।

नेपाल में हुए भारी नुकसान (पुलों व सड़कों के क्षतिग्रस्त होने) के बाद गंडक व अन्य नदियों में पानी का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले पूरी सतर्कता बरत रहे हैं।

संभावित स्थिति की ली जानकारी

नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बुधवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने अधिकारियों एवं पुलिस बल के साथ खड्डा तहसील के संभावित बाढ़ प्रभावित दियारा क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने शिवपुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और नदी व बाढ़ की संभावित स्थिति की जानकारी ली।

नेपाल के नवलपरासी पश्चिम स्थित जिला विपद् व्यवस्थापन समिति से मिली सूचना के बाद नारायणी नदी के तटीय और दियारा क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बुधवार सुबह 9:40 बजे जारी सूचना के अनुसार नेपाल के नुवाकोट क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। बारिश का पानी नुवाकोट बाजार को प्रभावित करते हुए गल्छी से नीचे तक पहुंचने की सूचना है। ऐसे में इसका असर नारायणी नदी के जलस्तर पर पड़ने की आशंका जताई गई है।

नेपाल में हुई भारी बारिश के मद्देनजर खड्डा तहसील के नारायणी नदी के तटीय और दियारा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। नदी का पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों में पानी पहुंचने की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों से सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर जाने के लिए तैयार रहने की अपील की गई है।

प्रशासनिक स्तर से लोगों को खाने-पीने की आवश्यक सामग्री, जरूरी कागजात और कीमती सामान सुरक्षित रखने के साथ बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम के निर्देशों का पालन करने तथा अफवाहों से बचने की अपील भी की गई है।

खड्डा तहसील के दियारा क्षेत्र के गांव शिवपुर,हरिहरपुर, नरायनपुर, मरिचहवा, बसंतपुर में खास सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि नेपाल में हुई बारिश का असर नदी के जलस्तर पर पड़ सकता है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि संभावित बाढ़ की स्थिति में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अधिकारियों ने बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निशा की मौत से रक्षाबंधन पर्व पर तीन भाइयों की सूनी रहेगी कलाई

वेब वार्ता, कुशीनगर। कुशीनगर जिले में तमकुहीराज थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित माधोपुर बुजुर्ग शिव मंदिर अनियंत्रित कार की चपेट में आने से बिहार के अराजीपुर बोधाछापर निवासी निशा कुमारी की मौत से उनके तीन भाइयों की कलाई रक्षाबंधन पर्व पर सूनी रहेगी। सुकदेवपट्टी की अनामिका का 15 वर्षीय इकलौता भाई बड़ी बहन के घर लौटने का इंजतार कर रहा था कि मौत की सूचना मिली।

अराजीपुर बोधाछापर निवासी ओमप्रकाश गिरी मुंबई में रह कर काम करते हैं। उनकी चार संतानें हैं। राजू गिरी, धनेश गिरी, राकेश गिरी के अलावा बेटी निशा कुमारी थी। राजू व धनेश बाहर रह कर काम करते हैं। परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी मां कलावती देवी व पेशे से निजी विद्यालय में शिक्षक राकेश के जिम्मे है। परिवार में छोटी होने के कारण निशा सबकी दुलारी थी। छह माह पूर्व दुलार में परिजनों ने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीद कर दी थी। निशा जब मन करता तो मां कलावती देवी से अनुमति के बाद स्कूटी से पढ़ने आती थी।

मंगलवार को भी मां से अनुमति के बाद स्कूटी से पढ़ने निजी महाविद्यालय आई और हादसे का शिकार हो गई। निशा पढ़ने में होनहार थी और उसका सपना बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर अधिवक्ता बनने की थी। उसकी मौत से परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग गया। निशा की मौत से 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर तीनों भाइयों की कलाई सूनी रहेगी।

बड़े भाई राकेश सिसकते हुए बताते हैं कि परिवार में सबकी दुलारी थी। रक्षाबंधन पर्व नजदीक होने के कारण दो भाइयों से फोन कर घर आने की जिद्द कर रही थी। मुझसे इस रक्षाबंधन बढ़िया उपहार के लिए रोज कहती थी लेकिन उसकी मौत की खबर से पूरे परिवार में मातम फैल गया। उसकी डोली को कंधा देने का सपना अधूरा रह गया।

हादसे में मौत की शिकार हुई दूसरी छात्रा बगल के सुकदेवपट्टी की अनामिका के गांव में मातम पसरा हैं। हरेंद्र ठाकुर व सीमा देवी की तीन संतानें मृतका अनामिका, भाई अभिषेक व बहन आंशिक हैं। हरेंद्र ठाकुर कोलकाता रह कर काम करते हैं। परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी मां सीमा देवी संभालती हैं। अनामिका जब महाविद्यालय जाती है तो इकलौते छोटे भाई अभिषेक के लिए खाने-पीने की चीजें जरूर लाती थी। मंगलवार को भी अभिषेक बड़ी बहन के लौटने के इंतजार में घर के बाहर बैठा था। रोज की तुलना में देर होने के बाद बार-बार घर के अंदर जा कर अपनी मां से बड़ी बहन के घर लौट कर नहीं आने की शिकायत कर रहा था। इसी दौरान उसकी मौत की खबर आ गई।

टेनी एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार, प्रशिक्षक और ट्रेनिंग पायलट की मौत

वेब वार्ता, कानपुर। गुरुवार की सुबह सिविल एयरोडम से उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही गंगा बराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना में प्रशिक्षक और ट्रेनी पायलट की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की तस्वीरों और वीडियो में स्पष्ट है कि, एयरक्राफ्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। घटनास्थल पर गंभीर हालत में एक शख्स जमीन पर लेटा नजर आ रहा है। मौके पर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त विमान गर्ग एविएशन कंपनी का है और वर्ष 2023 से इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा था। हादसा गुरुवार दोपहर गंगा बैराज क्षेत्र के नत्थूपुरवा गांव के करीब हुआ। विमान किस वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हादसे के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे के कारणों का भी अभी पता नहीं चल पाया है।

हादसे में जान गंवाने वाले इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया (गुजरात) और ट्रेनी अभिषेक पुजारी (महाराष्ट्र) शामिल है। पुलिस के मुताबिक विमान 4-सीटर, ट्विन-इंजन 'टेक्नम' ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। सुबह लगभग 11 :30 बजे उड़ान भरने के 20 मिनट बाद एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान 4-सीटर ट्विन-इंजन 'टेक्नम' ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट दोनों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह विमान 'गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर' से सुबह लगभग 11 :30 बजे उड़ान भरा था। टेक-ऑफ के कुछ ही देर बाद, सुबह 11 :50 बजे के आसपास यह दर्दनाक हादसा हुआ।

आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, बस-ऑटो की टक्कर में 7 की मौत

पलनाडू जिले में तड़के हुआ हादसा, मृतकों में 6 महिलाएं शामिल; 8 घायल

पलनाडू। आंध्र प्रदेश के पलनाडू जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। हादसा एक निजी बस और ऑटो-रिक्शा के बीच हुई जोरदार टक्कर के कारण हुआ। मृतकों में छह महिलाएं शामिल हैं। घायलों में चार बच्चे भी बताए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, हादसा चिलकालूरिपेट क्षेत्र में अड्डा रोड के पास हुआ। विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही एक निजी बस ने यात्रियों से भरे ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। ऑटो में करीब 15 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दो लोगों ने गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य घायल की मौत चिलकालूरिपेट के सरकारी अस्पताल में हुई। कुल सात लोगों की जान चली गई।

जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे सभी

पुलिस जांच में सामने आया है कि हादसे का शिकार हुए लोग चिलकालूरिपेट मंडल के वेलुरु गांव के निवासी थे। वे प्रकाशम जिले के कोंडामांजुलुर में आयोजित एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद ऑटो-रिक्शा से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में निजी बस से उनकी टक्कर हो गई।

पुलिस ने मृतकों की पहचान बोंटू बाबू (62), बोंटू मानेम्मा (55), संपूर्णम्मा (70), गंगम्मा (50), लक्ष्मम्मा (75), चौतुपल्ली स्वार्थम्मा (45) और मारियम्मा (45) के रूप में की है।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने जताया दुख

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी हादसे पर दुख जताया और जिला प्रशासन से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं रहने देने के निर्देश दिए।

राज्य की गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता ने भी पलनाडू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से हादसे और राहत कार्यों की जानकारी ली तथा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

तमिलनाडु के 37 तो बंगाल के 32 नागरिक लापता

कैलाश मानसरोवर यात्रियों पर भी असर

नई दिल्ली। नेपाल में मंगलवार को आई भीषण फ्लैश फ्लड की वजह से 130 से ज्यादा भारतीय अभी भी लापता हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालु भी शामिल हैं। सैकड़ों लोग अलग-अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिससे स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है।

नेपाल के बीच के हिस्सों में आई इस बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और कई इलाकों का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया है, जिससे लापता लोगों की सही जानकारी जुटाने में भारी मुश्किलें आ रही हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के साथ-साथ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने अपने नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

सामने आई जानकारी के मुताबिक, कम से कम 59 भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए यात्री थे, जिनके बारे में संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप होने की वजह से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। तमिलनाडु से गए 57 पर्यटकों में से 37 का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जबकि 20 लोगों से संपर्क हो चुका है। ये सभी हिमालय के एक मंदिर की तरफ जा रहे थे। कोयंबटूर की एक संस्था ने बताया कि उसके 77 सदस्य एक अप्रवासन केंद्र पर मौजूद थे और उनका कोई अता-पता नहीं है, हालांकि संस्था के मुताबिक 495 लोग सुरक्षित लौट चुके हैं। नेपाल सरकार ने भी बताया कि उस अप्रवासन दफ्तर का पूरा स्टाफ भी संपर्क से बाहर है, जिससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ जाती है।

...इलाकों से दूर हैं

उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग से लौटना संभव नहीं होने की वजह से वे अब फ्लाइट के जरिए काठमांडू और वहां से दिल्ली लौटेंगे और अपने वाहन वहीं छोड़ देंगे। महाराष्ट्र के सात पर्यटकों का एक दल भी फंसा हुआ था, जिनमें से मुंबई और पुणे के चार लोगों से संपर्क हो चुका है, जबकि बाकी तीन से संपर्क करने की कोशिश जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया है। केरलम के 36 पर्यटकों का दल सुरक्षित बताया गया है और वे प्रभावित इलाकों से दूर हैं।

पश्चिम बंगाल से गए 32 लोगों का एक ग्रुप भी लापता है। यह दल कुछ समय पहले यात्रा पर रवाना हुआ था और अगले दिन नेपाल पहुंचा था। जब यह टीम रसुवागढ़ी में तिब्बत जाने के लिए अप्रवासन दफ्तर में मौजूद थी, तभी अचानक बाढ़ आ गई। तब से इस ग्रुप के किसी भी सदस्य से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे उनके परिजन काफी चिंतित हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन जारी की है ताकि लापता लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया है। इस बीच, किसान नेता राकेश टिकैत भी अपने साथियों के साथ नेपाल के पोखरा में फंस गए थे।

राम मंदिर में 4 करोड़ का चेक, खाते में निकले मात्र 3 रुपए : अब असमंजस में ट्रस्ट

अयोध्या। अयोध्या के भव्य राम मंदिर को एक श्रद्धालु द्वारा भेंट किए गए 4 करोड़ रुपये के चेक ने एक नया मोड़ ले लिया है। चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु ने रामलला की सेवा में 10 हजार रुपये का समर्पण करने के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट को 4 करोड़ रुपये का एक चेक भी दिया था। यह मामला तब सामने आया जब ट्रस्ट ने बैंक खाते में चेक जमा कराने से पहले जांच की, तो पता चला कि जिस खाते से चेक जारी किया गया है, उसमें मात्र तीन रुपये का न्यूनतम बैलेंस ही है। इस अप्रत्याशित स्थिति के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में गंभीर मंथन का दौर जारी है।

दरअसल, इस दान के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी हुई थी। महिला श्रद्धालु एस नाग लक्ष्मी ने यह स्पष्ट किया था कि यह 4 करोड़ रुपये की धनराशि राम मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधाओं पर ही व्यय की जाए। उन्होंने ट्रस्ट से इस आशय का एक लिखित आशवासन भी मांगा था। राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने इस शर्त पर अपना जवाब दिया। उन्होंने बताया कि यह अपनी तरह का पहला ऐसा दान है जो सशर्त दिया जा रहा है, और ट्रस्ट के बाईलाज या खातों के संचालन को निर्धारित करने वाले नियम कायदों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ट्रस्ट को प्राप्त दान की धनराशि को विशेष रूप से कर्मचारियों पर ही व्यय किया जाए। इसी कारण, अंतरिम महासचिव ने महिला श्रद्धालु को लिखित आशवासन देने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रावधान बनता है, तो उसके आलोक में अवश्य ही लिखित आशवासन दिया जा सकेगा।

अंतरिम महासचिव के इस जवाब के बाद महिला श्रद्धालु वापस लौट गईं, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट को दिया गया 4 करोड़ रुपये का चेक वापस नहीं लिया। इसके बाद ही ट्रस्ट ने महिला श्रद्धालु के खाते की पड़ताल करवाई, जिसमें खाते में न्यूनतम बैलेंस न होने की बात सामने आई। अब यह आशंका जताई जा रही है कि यदि ट्रस्ट की कार्यकारिणी इस संदर्भ में विचार-विमर्श कर कोई ऐसी व्यवस्था निर्धारित करती है जो श्रद्धालु की शर्तों को पूरा करती हो, तो संभावना है कि महिला श्रद्धालु संबंधित खाते में दान की धनराशि जमा करा देंगी। इस पूरे प्रकरण पर ट्रस्ट गंभीरता से विचार कर रहा है, क्योंकि यह दान राशि और उसके साथ जुड़ी शर्तें एक अनूठी स्थिति पैदा करती हैं। श्रद्धालु द्वारा दिए गए चेक के साथ बैंक खाते में इतनी कम राशि का होना कई सवाल खड़े करता है।

जानकारी के अनुसार, महिला श्रद्धालु अपने समूह के साथ अयोध्या के ऋणमोचन घाट मोहल्ले में स्थित अम्माजी मंदिर (रामास्वामी टेंपिल) में ठहरी हुई थीं और अपने समूह के साथ ही वापस लौट गईं। मंदिर के प्रबंधक भी महिला श्रद्धालु के बारे में विशेष विवरण नहीं दे सके। यह देखना बाकी है कि ट्रस्ट इस स्थिति से कैसे निपटेगा और क्या श्रद्धालु की शर्तों को मानकर यह बड़ी दान राशि राम मंदिर के कोष में आ पाएगी।

16 की मौत, 105 भारतीय लापता, व्यापक बचाव अभियान जारी

काठमांडू। नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लेन्दे खोला (भोटेकोशी नदी) में उफान से टिमुरे बाजार और रसुवा सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है। आपदा में अब तक 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 105 भारतीय पर्यटकों के लापता होने की खबर है। स्थिति की गंभीरता को देखकर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया है, जिसमें 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। बाढ़ के तेज बहाव में कई वाहन और अन्य सामान बह गए हैं।

मैं जेल जाने के लिए अमेरिका से भारत आया हूं: अभिजीत

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके, जो महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं, ने अपने खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर को लेकर एक बेबाक बयान दिया है।

दीपके ने कहा है कि वह जेल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अमेरिका से इसी तैयारी के साथ आए थे कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वह बाहर हैं, उन्हें लगता है कि यह समय उन्हें लीज पर मिला हुआ है। दीपके ने एक चर्चा के दौरान कहा कि स्कूल ठीक करो अभियान के लिए यदि उन्हें जेल भेजा जाता है तो वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के संदर्भ में कहा, करें एफआईआर, भेज दो जेल। मैं तो अमेरिका से यह सोचकर आया था कि जेल जा रहा हूं। मैं तो मानसिक रूप से तैयार हूं। यह मुझे जो बाहर मिल रहा है समय मैं तो समझ रहा हूं कि मुझे लीज पर मिला है। मैं तो अमेरिका से जेल जाने के लिए तैयार होकर ही आया था। इनको हमारे ऊपर जितनी एफआईआर करनी है करने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। जेल भेजेंगे चला जाऊंगा। सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने स्कूलों में एंट्री बैन करने के आदेशों की तुलना डेड बॉडी छिपाने जैसी हरकत से की। उन्होंने कहा, यह क्या बात हुई कि हम स्कूल में जा रहे हैं, जहां हम गंदे टॉयलेट दिखा रहे हैं, वह नहीं दिखा सकते। जहां हम बेंच नहीं हैं, उसकी फोटो नहीं डाल सकते। जहां शिक्षक नहीं हैं, उसका वीडियो नहीं डाल सकते। आप नहीं चाहते कि सच बाहर आए, किस बात का शर्म है आपको। अभिजीत दीपके से यह भी पूछा गया कि वह भाजपा शासित राज्यों में अभियान चला रहे हैं, लेकिन पंजाब (आम आदमी पार्टी शासित) में क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर दीपके ने स्पष्ट किया कि वह पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी जाएंगे, लेकिन पहले वह अपने राज्य और अपने आसपास के क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं, जहां वह रहते हैं। दीपके ने कहा, पंजाब भी जाएंगे हम।

शी जिनपिंग और बांग्लादेश के प्रतिनिधि की भारत यात्रा पर संशय

नई दिल्ली। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और जो 12-13 सितंबर को होने वाला है, की तैयारियां अपने चरम पर हैं। हालांकि, इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन में कुछ प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। विशेष रूप से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बांग्लादेश के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि की भारत यात्रा पर अटकलें लगाई जा रही हैं।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि इन दोनों नेताओं के दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा की संभावनाओं ने पिछले कुछ दिनों में काफी जोर पकड़ा है। ऐसी खबरें हैं कि वह ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आ सकते हैं, और उनके साथ लगभग 400 अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो यह 2019 के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी। हालांकि, चीन की ओर से उनके दौरे की कोई औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, यही कारण है कि सम्मेलन से कुछ ही सप्ताह पहले भी उनकी यात्रा को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई निश्चितता नहीं है। रिपोर्टों में यात्रा की तैयारियों के संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन अंतिम कार्यक्रम और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। गौरतलब है कि शी जिनपिंग ने पिछले साल हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, हालांकि वे अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रहे हैं। इसी क्रम में, वह अगले सप्ताह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे से ठीक पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बीजिंग दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 25 अगस्त को डोभाल और चीन के विदेश मंत्री तथा भारत-चीन सीमा वार्ता के विशेष प्रतिनिधि वांग यी के बीच 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई। जानकारी के अनुसार, बातचीत का मुख्य विषय भारत-चीन सीमा प्रश्न और दोनों देशों के बीच संबंधों से जुड़े मुद्दे रहे। यह यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारत और चीन के रिश्ते लंबे समय तक तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा पर सैनिकों की तैनाती और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से जुड़े विवादों के बीच दोनों देशों ने हाल के वर्षों में तनाव कम करने की कोशिशें की हैं। दूसरी ओर, बांग्लादेश की ओर से आमंत्रित नेता की उपस्थिति का मामला अधिक अनिश्चित है। भारत ने उन्हें ब्रिक्स के आउटरीच सत्र में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय बांग्लादेश बिम्सटेक का अध्यक्ष है। भारत ने स्पष्ट किया है कि ब्रिक्स की आउटरीच बैठक के लिए क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित करने की परंपरा के तहत उन्हें बुलाया गया है।

जवान ने लगाई गुहार: देश की रक्षा करूं या परिवार की

बॉर्डर पर तैनात जवान का भावुक वीडियो वायरल

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी और देश की सीमा (एलओसी) पर तैनात एक सैनिक वीर बहादुर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में फौजी ने आरोप लगाया कि कुछ भू-माफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उनके बुजुर्ग मां-बाप तथा गर्भवती बहन के साथ मारपीट की है। उन्होंने अपनी हताशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे सीमा पर देश की रक्षा करें या अपने परिवार की चिंता करें। वीर बहादुर सिंह ने यहां तक कह दिया कि वे या तो भू-माफियाओं को गोली मार देंगे या खुद को खत्म कर लेंगे। फौजी ने अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई और बताया कि वे उनसे पहले भी मिल चुके हैं और सेना की तरफ से भी दो बार पत्र भेजा जा चुका है। उनका दर्द था कि घर पर उनकी बुजुर्ग मां-बाप, एक गर्भवती बहन और एक छोटी बहन अकेली हैं, जिनके साथ उनके चाचा कथित तौर पर मारपीट करते हैं। इस वीडियो ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और सहानुभूति बटोरी, जिससे प्रशासन पर मामले की जांच का दबाव बढ़ा। हालांकि, मामला तूल पकड़ते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई। सलेमपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) गौरव सिंह ने तत्काल जांच कर स्थिति स्पष्ट की। पुलिस के अनुसार, यह विवाद उनके पिता और चाचाओं के बीच एक पुश्तैनी घर के बंटवारे का है, न कि किसी भू-माफिया का। पुलिस जांच में सामने आया कि फौजी के पिता राजा सिंह और उनके दो भाई रामनारायण सिंह व सुग्रीव सिंह का चुरिया गांव में एक पुश्तैनी मकान है। पिछले कुछ समय पहले हुई पंचायत में राजा सिंह और रामनारायण सिंह ने अपने हिस्से की जमीन तीसरे भाई सुग्रीव सिंह को बेचने का फैसला किया था। इस समझौते के तहत तय रकम में से फौजी वीर बहादुर सिंह के बैंक खाते में भी आधी राशि भेजी गई थी। पुलिस का कहना है कि घर खाली करने पर बाकी पैसे देने का समझौता हुआ था, लेकिन अब फौजी के पिता राजा सिंह समझौते को मानने से इंकार कर रहे हैं।

गंडक नदी में फिर बढ़ी हलचल, उत्तर प्रदेश और बिहार में फिर अलर्ट

नई दिल्ली। नेपाल में हालिया जल प्रलय के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में पैदा हुई चिंताएं अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।

गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है, जिसके चलते दोनों राज्यों को फिर से सतर्क रहने को कहा गया है। पहले गंडक नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा था और वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से भी पानी का बहाव कम हो गया था, जिससे कुछ राहत मिली थी। उस समय नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार के सीमावर्ती इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया था। हालांकि, यह राहत अल्पकालिक साबित हुई है, क्योंकि देवघाट क्षेत्र में देर रात हुई बारिश के कारण वॉटर लेवल एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। इस वृद्धि का सटीक असर कितना होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

पूर्व में, वाल्मीकिनगर गंडक बैराज में पानी का बहाव घटकर 81 हजार क्यूसेक पर आ गया था। एक वजह यह भी बताई गई थी कि नेपाल की त्रिशूली नदी का पानी नारायणी नदी के जरिए आगे बढ़ा है, जिससे गंडक नदी पर दबाव में कमी आई थी। हालांकि, अब ताजा खतरे को देखते हुए अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर बने हुए हैं। गंडक नदी नेपाल से निकलकर भारतीय मैदानी इलाकों तक पानी लाती है, इसलिए ऊपरी हिस्से में बाढ़ जैसी स्थिति निचले हिस्सों के जिलों के लिए बड़ी चिंता का कारण बनती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्थिति और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जिन सीमावर्ती इलाकों में इसका असर पड़ने की आशंका है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव दलों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा राहत बल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।

नेपाल में जल प्रलय से गंडक नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए बिहार में सतर्कता बढ़ा दी गई थी। राज्य के आठ जिलों, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं, के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया था। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और बेतिया में राष्ट्रीय आपदा राहत बल और सशस्त्र सीमा बल की बटालियनें तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी अधिकारी अलर्ट मोड पर थे। निचले इलाकों को देर रात खाली करा लिया गया था। मुख्यमंत्री ने महराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर सहित आसपास के जिलों को तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

अमेरिका ने बताया सीआईए प्रमुख के मॉस्को दौरे का मकसद

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के निदेशक जॉन रैटक्लिफ का हालिया मॉस्को दौरा किस उद्देश्य से हुआ था। ट्रंप ने संकेत दिया कि खुफिया प्रमुख यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने संबंधी उच्च-स्तरीय चर्चा के लिए रूसी राजधानी में मौजूद थे। एक बातचीत में ट्रंप ने कहा कि रैटक्लिफ का यह दौरा लगभग एक नियमित प्रक्रिया जैसा था, जिसका उद्देश्य लोगों को निराश करना नहीं, बल्कि यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त होते देखना था।

खूबसूरत वादियों में श्री मत्स्यगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर बन रहा आकर्षण का केंद्र

हैदराबाद। हैदराबाद के करीब स्थित श्री मत्स्यगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यदाद्रि भुवनगिरि जिले के वालिगोंडा मंडल अंतर्गत वेमुलाकोंडा गांव में एक विशाल पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां भगवान नरसिम्हा की पूजा मछली के रूप में की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मत्स्यगिरी में भगवान खुद प्रकट हुए थे। इसी आस्था के कारण यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर में स्थित प्राकृतिक जलकुंड को स्थानीय लोग नामाला गुंडम के नाम से जानते हैं। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक कुंड में रहने वाली कुछ मछलियों के सिर पर प्राकृतिक रूप से ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के तिलक के समान माना जाता है। श्रद्धालु इन मछलियों को पवित्र मानते हैं और उन्हें दाना खिलाना शुभ समझते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक मछलियों के शरीर पर दिखाई देने वाली ऐसी रेखाएं और निशान उनकी प्राकृतिक शारीरिक संरचना का हिस्सा हैं, जिन्हें धार्मिक आस्था के आधार पर विशेष महत्व दिया जाता है।

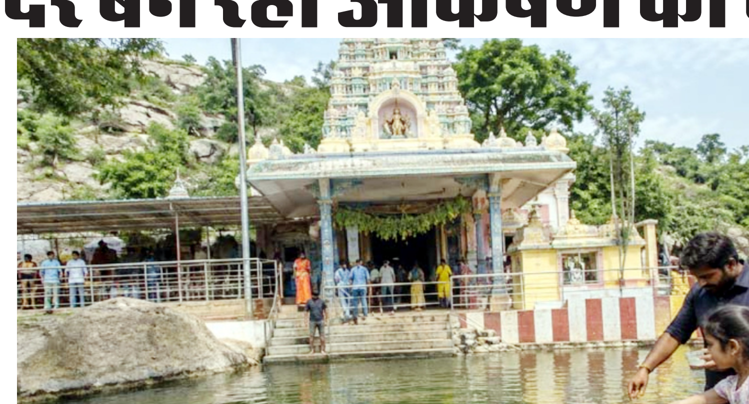

रिपोर्ट के मुताबिक ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मत्स्यगिरी मंदिर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर घुमावदार मार्ग है। रास्ते से आसपास फैले हरे-भरे खेतों, ग्रामीण इलाकों और प्राकृतिक दृश्यों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है।

भिंड में जमीन नामांतरण के लिए पांच हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

भिंड। मेहगांव में जमीन के नामांतरण के एवज में रिश्वत मांगना पटवारी को महंगा पड़ गया। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार सुबह मेहगांव तहसील के पास हल्का सिमराव के पटवारी संजय बघेल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त टीम ने पटवारी के हाथ धुलवाए तो पानी का रंग गुलाबी हो गया। इसके बाद टीम पटवारी को मेहगांव रेस्ट हाउस ले गई, जहां आगे की कार्रवाई की गई।

पटवारी पर नामांतरण के लिए 30 हजार मांगने का आरोप

फरियादी राघवेंद्र बघेल निवासी सरसेड़ थाना मेहगांव ने लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में शिकायत की थी। राघवेंद्र ने बताया कि करीब ढाई महीने पहले उसने सिमराव गांव में अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदी थी। जमीन के नामांतरण के लिए वह पटवारी संजय बघेल के पास पहुंचा। आरोप है कि पटवारी ने नामांतरण के लिए उससे 30 हजार रुपये की मांग की। राघवेंद्र ने इतनी रकम देने से मना कर दिया और मामले की शिकायत लोकायुक्त में कर दी।

इसकी जानकारी फरियादी ने लोकायुक्त टीम को दी

शिकायत के बाद लोकायुक्त टीम ने मामले की पुष्टि की। करीब पांच दिन पहले पटवारी ने राघवेंद्र को फोन कर नामांतरण के लिए मिलने बुलाया। मुलाकात के दौरान पटवारी ने 10 हजार रुपये की मांग की। इसकी जानकारी फरियादी ने लोकायुक्त टीम को दी। इसके बाद टीम ने रिश्वत लेते पकड़ने की योजना बनाई।

तहसील के पास बुलाकर मांगे रुपये

गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पटवारी ने फरियादी को मेहगांव तहसील के पास रुपए लेकर बुलाया। फरियादी ने लोकायुक्त के निर्देश पर केमिकल लगे पांच हजार रुपये पटवारी को दिए। जैसे ही पटवारी ने रुपये लिए, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया। टीम ने मौके पर ही उसके हाथ धुलवाए, जिसमें गुलाबी रंग आने से रिश्वत लेने की पुष्टि हुई।

एमपी के उमरिया में मिलावटी मिठाइयों पर बड़ी कार्रवाई

शिवालय रेस्टोरेंट से 54 किलो सिंथेटिक मिठाई बरामद, तीन दिन के लिए सील

उमरिया। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच मिलावटी और सिंथेटिक मिठाइयों की बिक्री की शिकायतों ने खाद्य सुरक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शिकायतों के आधार पर विभाग की टीम ने शहर के दो प्रमुख प्रतिष्ठानों शिवालय रेस्टोरेंट और राजा स्वीट्स में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई एसडीएम अम्बिकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों में उपलब्ध मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की और आवश्यक नमूने लिए।

शिवालय रेस्टोरेंट से 54 किलो मिठाई बरामद

जांच के दौरान शिवालय रेस्टोरेंट से करीब 54 किलो सिंथेटिक मिठाई बरामद की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बरामद मिठाई के नमूने लेकर उन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित मिठाई खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।

गोदाम और निर्माण स्थल की भी जांच

शिवालय रेस्टोरेंट में टीम ने केवल तैयार मिठाइयों की गुणवत्ता ही नहीं जांची, बल्कि प्रतिष्ठान के गोदाम और मिठाई निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री के रखरखाव और मिठाई बनाने की प्रक्रिया से संबंधित कई अनियमितताएं सामने आने की बात कही जा रही है। टीम ने मौके से आवश्यक खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए। इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होगा कि बरामद मिठाई निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती है या नहीं।

राजा स्वीट्स में भी हुई जांच

इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने राजा स्वीट्स में भी निरीक्षण किया। यहां भी खराब गुणवत्ता की मिठाई पाए जाने पर उसका नमूना लिया गया। विभाग ने संबंधित मिठाई को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित नियमों के अनुसार खाद्य सामग्री तैयार करने और उसका रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा।

शिवालय रेस्टोरेंट तीन दिन सील

शिवालय रेस्टोरेंट में सिंथेटिक मिठाई मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को तीन दिनों के लिए सील कर दिया है। शिकायत के बाद एसडीएम अम्बिकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने रेस्टोरेंट के साथ गोदाम और मिठाई निर्माण स्थल की भी जांच की थी। कार्रवाई के दौरान करीब 54 किलो सिंथेटिक मिठाई बरामद होने के बाद विभाग ने उसके नमूने प्रयोगशाला भेजे। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगा। रेस्टोरेंट को तीन दिन के लिए सील किए जाने के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

मिठाई और खोवे की गुणवत्ता पर सवाल

शहर में हुई इस कार्रवाई के बाद उमरिया जिले में बिकने वाली मिठाइयों और खोवे की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर लगातार ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं कि कई स्थानों पर सिंथेटिक दूध, खोवा और उससे तैयार मिठाइयों की बिक्री की जा रही है। त्योहारी दिनों में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावटी और सिंथेटिक खाद्य पदार्थों का कारोबार बढ़ने की आशंका भी बनी रहती है। खाद्य विभाग की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब बाजार में त्योहारों को लेकर मिठाइयों की बिक्री बढ़ी हुई है।

जिलेभर में जांच की जरूरत

शहर के अलावा जिले के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में संचालित मिठाई दुकानों, डेयरियों और खोवा विक्रेताओं की भी नियमित जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय यदि खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार अभियान चलाकर मिठाई और खोवे के नमूने लेता रहे, तो मिलावट के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। फिलहाल शिवालय रेस्टोरेंट और राजा स्वीट्स से लिए गए नमूने प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं। विभाग की आगे की कार्रवाई इन जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। वहीं, शिवालय रेस्टोरेंट को तीन दिनों के लिए सील किए जाने के बाद जिले के अन्य खाद्य कारोबारियों में भी कार्रवाई को लेकर चर्चा है। अब सभी की नजर प्रयोगशाला रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग अगला कदम उठाएगा।

आलीरापुर जिले में सूने मकान में घुसे थे चार चोर, लोगों से बचकर भागने में एक आरोपी की हुई मौत

अलीराजपुर। जोबट नगर के गणेश मंदिर क्षेत्र में बुधवार रात सेवानिवृत्त शिक्षक तुकाराम ढोले के सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। आरोपियों ने घर के कमरों और अलमारियों को खंगालते हुए ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसी दौरान आसपास के लोगों को इसकी भनक लग गई। लोगों ने मकान को घेरकर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया।

खुद को घिरता देख चारों आरोपी भागने लगे। इसी दौरान ग्राम ढेलवानी (थाना बाग) निवासी पानसिंह अजनार (40) गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। भागने के दौरान दो अन्य आरोपी भी घायल हुए, जिनका जोबट अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया।

मकान से नकदी और जेवर चोरी

फरियादी तुकाराम ढोले ने बताया कि वे परिवार के साथ इंदौर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपियों ने सूने मकान को निशाना बनाया। उन्होंने घर में रखी अलमारियों के ताले तोड़ दिए। एक सूटकेस में रखे कपड़ों के साथ करीब 30 हजार रुपये चोरी किए गए। इसके अलावा अलमारी में रखे सोने के

कंगन, दो सोने की चेन, चार जोड़ चांदी की पायल और 10 से 12 चांदी के सिक्के भी चोरी होने की जानकारी दी गई है। मामले में जोबट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पानसिंह अजनार की उपचार के दौरान मौत की सूचना मिलने पर उसके परिजन जोबट अस्पताल पहुंचे। शव देखते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

दो का उपचार जारी, एक की तलाश

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दो घायल आरोपियों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस चोरी में शामिल चारों आरोपियों की भूमिका, चोरी गए सामान और भागने के दौरान हुई घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है। मृतक पानसिंह अजनार के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। उसके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है। पुलिस जांच के बाद ही चोरी की वारदात और आरोपियों की भूमिका को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

लड़की के कोर्ट मैरिज करने पर गुस्साए घर वाले

ससुराल में घुस उसे किडनैप कर ले गए; झाबुआ जिले की घटना

झाबुआ। झाबुआ जिले के खरडुबडी गांव में एक युवक और उसकी पत्नी के बीच कोर्ट मैरिज से उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां मायके पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर न सिर्फ पूरे परिवार के साथ मारपीट की बल्कि नवविवाहिता का अपहरण कर अपने साथ ले गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है।

फरियादी डिंपल पिता नानुराम टांक ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपनी किराना दुकान चलाता है और उसने अपनी मर्जी से 27 जुलाई 2026 को रियांशी के साथ कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद से उसकी पत्नी उसके साथ ही रह रही थी। इस बात से रियांशी का पिता उदयसिंह और उसका परिवार लगातार नाराज चल रहा था। डिंपल ने यह भी बताया कि 13 अगस्त को ही रियांशी के बयान भी दर्ज हो चुके थे तथा हाईकोर्ट ने हमें सुरक्षा देने के लिए पुलिस को निर्देशित भी किया था।

कार में सवार होकर पहुंचे लोग

बुधवार की दोपहर में जब डिंपल, उसकी पत्नी रियांशी, मां शर्मिला और भाभी शीतल घर पर मौजूद थे, तभी उदयसिंह नायक, शंकर नायक, धन्ना नायक और भमरसिंह नायक समेत करीब दस से अधिक लोग तीन कारों में सवार होकर वहां पहुंचे और चारों के साथ थप्पड़ और मुक्के से जमकर मारपीट की। इस हमले में डिंपल को सीने पर और भाभी शीतल को मुंह तथा गाल पर गंभीर चोटें आईं।

रियांशी को जबरन उठाकर ले गए

आरोप है कि मारपीट के दौरान उदयसिंह और उसके साथियों ने रियांशी को जबरन पकड़ लिया और उसे अपने साथ उठाकर ले गए। पुलिस द्वारा बुधवार शाम को पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 333, 140(3), 115(2) और 3(5) के तहत उदयसिंह और उसके तीन अन्य साथियों को नामजद आरोपी बनाकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

745 करोड़ रुपये में बनेगी इंदौर-देपालपुर के बीच 37 किमी लंबी फोरलेन रोड

इंदौर। इंदौर और देपालपुर के बीच 37 किमी लंबी फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। इस पर 745 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सिंहस्थ के दौरान उज्जैन और इंदौर के आस-पास सड़कों को नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।

इस सड़क को बनाने की घोषणा पिछले वर्ष 2025 नवंबर में हुई थी। अब मंजूरी मिलने के बाद सड़क बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बनने से इंदौर से देपालपुर सहित उससे आगे जाने वालों के लिए भी राह आसान होगी।

यह सड़क देपालपुर से इंगोरिया जाने वाले वाहनों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। इससे जावरा, नागदा और उज्जैन जाने वाले लोगों को एक नया रास्ता

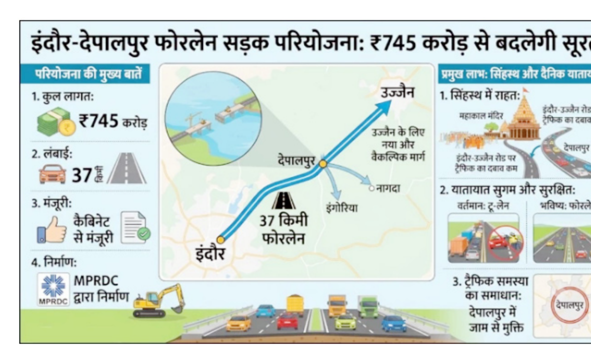

मिलेगा। इस सड़क के बनने से देपालपुर में ट्रैफिक की समस्या भी सुलझने की उम्मीद है। अभी इंदौर से देपालपुर का रास्ता टू-लेन का है। इस पर ट्रकों सहित यात्री बसें और अन्य वाहन गुजरते हैं। ऐसे में इस सड़क पर वाहनों का सबसे ज्यादा दबाव रहता है। कई बार जाम की स्थिति बन जाती है और ओवरटेकिंग में भी खतरा बना रहता है। सिंहस्थ के दौरान इंदौर से उज्जैन जाने वाले वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में लोग फोरलेन से देपालपुर होते हुए उज्जैन पहुंच सकेंगे।

हमीदिया अस्पताल में फिर बनेगा जेल वार्ड, कैदियों की निगरानी होगी आसान

भोपाल। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने आने वाले कैदियों की सुरक्षा को लेकर जेल विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। अस्पताल से बंदियों के फरार होने की आशंकाओं और सुरक्षा में होने वाली चूक को रोकने के लिए अब यहां दोबारा 'जेल वार्ड' शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

आपको बता दें कि साल 2021 में इस विशेष वार्ड को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से बीमार कैदियों को आम मरीजों के बीच ही सामान्य वार्ड में भर्ती करना पड़ रहा था, जिससे पुलिस को भीड़भाड़ के बीच उनकी निगरानी करने में भारी मशक्कत करनी पड़ती थी।

स्वास्थ्य विभाग को भेजा जा रहा प्रस्ताव

जेल वार्ड को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए जेल विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा जा रहा है। भोपाल सेंट्रल जेल के अधीक्षक मानेंद्र सिंह के मुताबिक, जैसे ही इस प्रस्ताव को शासन की हरी झंडी मिलेगी, हमीदिया अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर नए वार्ड की जगह, बिस्तरों की क्षमता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तय किए जाएंगे। फिलहाल, कैदियों को सामान्य वार्ड में रखने से न सिर्फ अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगानी पड़ती है, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही के कारण हमेशा एक रिस्क बना रहता है।

वार्ड में आम मरीजों की होगी 'नो-एंट्री'

प्रस्तावित जेल वार्ड पूरी तरह से सिर्फ बंदियों के लिए ही आरक्षित रहेगा। इस वार्ड में किसी भी सामान्य मरीज को भर्ती नहीं किया जाएगा। यहां मुख्य रूप से भोपाल सेंट्रल जेल के अलावा मध्य प्रदेश की अन्य जेलों से गंभीर बीमारियों के विशेष इलाज या मेडिकल जांच के लिए लाए जाने वाले सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों को ही रखा जाएगा।

सुरक्षा के लिहाज से होंगे ये तीन बड़े फायदे

एक अलग और सुरक्षित जेल वार्ड बन जाने से पुलिस और जेल प्रशासन को सुरक्षा प्रबंधन में काफी सहूलियत मिलेगी: निगरानी होगी आसान: बीमार कैदियों को अस्पताल के अलग-अलग वार्डों में रखने के बजाय एक ही तय और सुरक्षित जगह पर रखा जा सकेगा। इससे उन पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा। बाहरी संपर्क पर लगेगी रोक: कैदियों का आम मरीजों और उनके मिलने वालों (परिजनों) से सीधा संपर्क लगभग खत्म हो जाएगा। इससे सुरक्षा में सेंध लगने या किसी साजिश का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी होगी केंद्रित: पुलिस जवानों को पूरे अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों में तैनात करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। गार्ड्स का पूरा फोकस सिर्फ जेल वार्ड की सुरक्षा पर रहेगा, जिससे मैनपावर का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा।

रिटायर्ड महिला सब इंस्पेक्टर के 17 लाख रुपये नहीं लौटाने पर हाईकोर्ट नाराज

अधिकारियों को चार सप्ताह की मोहलत : 28 सितंबर को अगली सुनवाई

जबलपुर। हाई कोर्ट ने रिटायर्ड महिला सब इंस्पेक्टर के वेतन से काटी गई करीब 17 लाख रुपये की राशि अब तक वापस नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर पूरी राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं हुआ तो 28 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, तत्कालीन भोपाल एसपी ममतेश माली और पेंशन अधिकारी शोभा

भाकरिया को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा।

2016 में सेवानिवृत्त हुई थीं

मामला भोपाल की रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर लजवर खानम की अवमानना याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता 30 अप्रैल 2016 को पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुई थीं। याचिका के मुताबिक उनके वेतन से करीब 17 लाख रुपये की वसूली की गई थी। उन्होंने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

11 मई 2024 को आया था आदेश

हाई कोर्ट ने 11 मई 2024 को मामले में आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता के वेतन से काटी गई पूरी राशि वापस करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्हें राशि अब तक नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने आदेश की अवहेलना को लेकर अवमानना याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट की अपील खारिज

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील 12 फरवरी 2026 को खारिज हो चुकी है। हालांकि, फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लंबित है।

पुनर्विचार याचिका से आदेश पर रोक नहीं

हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर कोई स्थगन नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल पुनर्विचार याचिका लंबित होने के आधार पर आदेश का पालन रोका नहीं जा सकता। संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह में आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। राशि वापस नहीं होने पर 28 सितंबर को अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

उज्जैन में पुरानी दुश्मनी दूर करने के लिए कर रहे थे पार्टी, शराब पीने के बाद फिर हुए विवाद में दो की हत्या

उज्जैन। उज्जैन के कानीपुरा स्थित एक ढाबे पर भोजन कर रहे एक ही संगठन के दो गुटों के सदस्यों के बीच आपसी विवाद में दो लोगों की हत्या हो गई। लगभग एक दर्जन से अधिक लोगों ने दो लोगों पर हथियारों से हमला कर दिया। बताया जाता है कि ढाबे पर किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के चलते मारपीट के बाद हत्या हो गई।

बताया जाता है कि करणी सेना जिला उपाध्यक्ष नीमनवासा निवासी राहुल दरबार उर्फ विजय प्रताप (42) दूसरे पक्ष के शक्तिसिंह के साथ खाना खा रहे थे। इनके बीच पुराने विवाद में हुए समझौते के के कारण दोनों ने ढाबे में एक साथ पार्टी करने का निश्चय किया था। यहां दोनों शराब पी और खाना खाया। इस बीच बातों-बातों में हुए शक्ति और राहुल के बीच फिर से विवाद हो गया। विवाद में मारपीट भी हुई।

इस दौरान शक्ति ने अपने साथियों को ढाबे पर बुलाया। शक्ति का साथी सोनू बंजारा अपने एक दर्जन से अधिक साथियों के साथ ढाबे पर पहुंचा और यहां राहुल पर हमला कर दिया। राहुल के साथ ही उंडासा निवासी ढाबा मालिक जितेंद्र पवार (35) पर भी हथियारबंद साथियों ने हमला कर दिया। हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल हुआ जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। साथ ही जितेंद्र का शव ढाबे के पास मिला। चिमनगंज थाना प्रभारी विवेक कनोड़िया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले में जांच कर रही है। हमले में शक्तिसिंह भी घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।

बीबीएल में अब खिलाड़ियों को मिलेगी मोटी रकम

सीए ने टीमों को दी फैसले की आजादी

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट लीग (बीबीएल) में अब खिलाड़ियों को मोटी रकम मिलेगी। इसका कारण ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने अनुबंध से जुड़ी रोक हटाते हुए नये नियम लागू कर दिये हैं। इसके तहत अब क्लब ऑस्ट्रेलियाई और विदेशी खिलाड़ियों को टूनार्मेंट में खेलने के लिए पहले से कहीं अधिक राशि दे सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन (एसीए) के साथ बातचीत के बाद, सीए ने इन सुधारों की घोषणा की। नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए चली आ रही ड्राफ्ट व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, बड़े घरेलू खिलाड़ियों को ज्यादा वित्तीय लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से जरूरी बड़े घरेलू खिलाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है, जिससे क्लबों के पास बेहतर प्रतिभाओं पर अधिक निवेश करने के लिए पर्याप्त राशि रहेगी।

अब क्लबों के पास विदेशी खिलाड़ियों को अनुबंधित न करने का विकल्प भी होगा। इस बदलाव का लाभ कुछ प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मिलेगा। हाल में मेलबर्न रेनेगेड्स छोड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर एडम जम्पा को अब कोई न्या क्बब मिल सकता है।

इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के टी-20 विकेटकीपर जॉश इंग्लिश को भी कोई नई टीम मिल सकती है। इसका कारण है कि पर्थ स्कॉर्चर्स के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। गौरतब है कि ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बीबीएल खिलाड़ी और विभिन्न क्लब लंबे समय से विदेशी खिलाड़ियों के लिए बनी ड्राफ्ट प्रणाली से सहमत नहीं थे, क्योंकि इसके कारण कई बार कम मशहूर विदेशी खिलाड़ियों को ड्राफ्ट नियमों की वजह से स्थानीय खिलाड़ियों से कहीं अधिक रकम मिल जाती थी जिससे टीम संतुलन और वित्तीय प्रबंधन में समस्या आती थी।

बीबीएल के प्रमुख एलिस्टर डॉब्सन ने कहा कि यही नियम महिला लीग पर भी लागू होंगे। साथ ही कहा कि क्लबों को अलग-अलग खिलाड़ियों की कीमत और उनके घरेलू या विदेशी होने के आधार पर समीक्षा करने की आजादी दी गयी है। इसके बावजूद, हमें उम्मीद है कि हमारी लीग में बेहतरीन विदेशी खिलाड़ी आते रहेंगे क्योंकि वे हर टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं।

भारतीय टीम के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाना कठिन होगा : द्रविड़

न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी कड़ी टक्कर

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि टीम इंडिया के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में पहुंचना कठिन होगा। द्रविड़ के अनुसार भारतीय टीम अभी अंक तालिक में पांचवे नंबर पर है और उसे खिताबी मुकाबले में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए अपने बचे हुए अधिकतर मैच जीतने होंगे। द्रविड़ ने कहा कि अगर भारतीय टीम मौजूदा स्थिति के बावजूद डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में सफल रहता है, तो यह एक शानदार उपलब्धि होगी। द्रविड़ ने साथ ही कहा, मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने में सफल रहेगी। मुझे लगता है कि भारतीय टीम थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन भारतीय टीम बहुत शानदार है और उसे किसी भी स्तर पर कम नहीं आंका जा सकता। उसने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी शुरूआत की, इसलिए पहला कदम बहुत अच्छा है।

हालांकि भारतीय टीम की असली परीक्षा अगले साल न्यूजीलैंड दौरे पर होगी। तब भारतीय टीम को जनवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर पांच टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। वहीं इससे पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड में दो टेस्ट मैच खेलेगी। इस दौरे में पांच एकदिवसीय और उतने ही टी-20 मैच भी रहेंगे। द्रविड़ ने इस दौरे को लेकर कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घरेलू मैदानों पर खेलना हमेशा ही चुनौती पूर्ण रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी का अहसास टीम को होगा। द्रविड़ ने कहा, भारत के कई युवा खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के कठिन हालातों में नहीं खेला है, इसलिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। न्यूजीलैंड की टीम कड़ी चुनौती पेश करती है।

न्यूजीलैंड के बाद, भारतीय टीम को अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में पांच टेस्ट मैचों की एक और कठिन सीरीज खेलनी होगी। इस पूर्व भारतीय कप्तान ने बताया कि घरेलू सीरीज भी आसान नहीं होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी भारत में अच्छा प्रदर्शन करने और जीत हासिल करने के लिए बेताब रहेंगे।

कार्तिक को कोच बनाये सीएसके : हेडन

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर और सीएसके के पूर्व सलामी बल्लेबाज रहे मैथ्यू हेडन ने कहा है कि दिनेश कार्तिक को टीम का नया मुख्य कोच बनाया जाना चाहिये। आईपीएल की पांच बार की खिताब विजेता चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) अपने कोच स्टीफन फ्लेमिंग के इस्तीफे के बाद से ही नये कोच की तलाश में है। इसके बाद से ही कोच पद के लिए पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी, इयोन मोर्गन और माइकल हसी के नाम की चचाएं चल रही हैं।

हेडन ने कहा कि कार्तिक को स्थानीय होने का लाभ मिलेगा। हेडन के अनुसार, उनका स्थानीय होना सीएसके के लिए कोच के तौर पर उन्हें एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। उन्होंने साथ ही कहा, मुझे पता है कि कई फ्रेंचाइजी अंतरराष्ट्रीय कोच चुनती हैं पर मुझे लगता है कि सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए मुख्य कोच की भूमिका में स्थानीय कोच होना बेहतर होगा। इसलिए मुझे लगा कि दिनेश इसके लिए एकदम सही रहेंगे। स्थानीय पहचान के अलावा, कार्तिक की कोचिंग क्षमताएं भी काफी अच्छी हैं। पिछले तीन सालों में, कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा रहे हैं, एक ऐसी टीम जिसने हाल के सीजन में मजबूत प्रदर्शन किया है और उनकी कोचिंग काबिलियत को दिखाता है। हेडन ने इस बात पर जोर दिया कि फ्रेंचाइजी के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना बेहद आवश्यक है।

हेडन ने फ्लेमिंग और धोनी की शानदार साझेदारी की भी सराहना की, जिन्होंने मिलकर सीएसके को रिकॉर्ड पांच आईपीएल खिताब दिलाए और मुंबई इंडियंस के बराबर सफलता हासिल की। गौरतलब है कि सीएसके ने अभी तक अपने नए मुख्य कोच को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है पर हेडन का यह सुझाव निश्चित रूप से बहस छेड़ देगा कि क्या टीम अपने नए युग की शुरूआत एक स्थानीय प्रतिभा के साथ करेगी, या फिर किसी और अनुभवी को कोच बनाएगी।

7 अक्टूबर से अहमदाबाद में होगी राष्ट्रमंडल क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप

अहमदाबाद। यहां 7 से 10 अक्टूबर तक अहमदाबाद के सावरकर खेल परिसर में राष्ट्रमंडल क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसमें 46 देश भाग लेंगे। चार दिवसीय इस प्रतियोगिता से क्यू स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने को बेहतरीन अवसर मिलेगा। इसमें लगभग 46 देशों के खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस आयोजन से भारत को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति और मजबूत करने का अवसर देगा।

भारतीय बिलियड्र्स और स्नूकर महासंघ (बीएसएफआई) के अनुसार, चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में बिलियड्र्स, स्नूकर, हेयबॉल, 10-बॉल पूल और ब्लैकबॉल जैसी विभिन्न स्पधाएं आयोजित की जाएंगी। चार मुख्य स्पधाओं में पुरुष और महिला वर्ग में 16-16 खिलाड़ी इसमें उतरेंगे। इस साल के कार्यक्रम में विशेष रूप से बिलियड्र्स को शामिल किया गया है, जिसमें दोनों वर्गों में आठ-आठ खिलाड़ियों का ड्रॉ होगा, जिससे प्रतियोगिता और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। इस चैंपियनशिप का आयोजन विश्व बिलियड्र्स खेल महासंघ (डब्ल्यूसीबीएस) और बीएसएफआई के तत्वावधान में एपेक्स स्पोर्ट्स द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को क्यू स्पोर्ट्स के लिए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बीएसएफआई ने 13 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें छह पुरुष और सात महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों का चयन सप्ताहांत में आयोजित कड़े ट्रायल के बाद किया गया।

श्रीजेश सहित दिग्गजों ने हॉकी के भविष्य पर चिन्ता जतायी

पेरिस। भारतीय टीम के एफआईएच विश्वकप से बाहर होने के बाद से ही पूर्व गोलकीपर पी आर श्रीजेश सहित कई दिग्गजों ने हॉकी के भविष्य को लेकर गंभीर चिन्ता जतायी है। इन्होंने जूनियर खिलाड़ियों को समय पर अवसर न दिए जाने पर भी चिंता जतायी और कहा है कि सीनियर खिलाड़ियों के जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा ये भी बड़ा सवाल है। श्रीजेश ने पूछा, क्या हमने दूसरी टीम तैयार की है? लॉस एंजिलिस ओलंपिक में अब केवल दो साल बचे हैं और उससे पहले मुश्किल से तीस अंतरराष्ट्रीय मैच ही होंगे, जिनसे ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि वर्तमान विश्व कप टीम में वही कोर खिलाड़ी हैं, जबकि मनमीत सिंह, आमिर अली, रोशन कुजूर जैसे कई प्रतिभाशाली जूनियर खिलाड़ी अब भी इंतजार ही कर रहे हैं।

वहीं पूर्व ओलंपियन जगबीर सिंह ने भी चयन के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए और कहा कि जूनियर खिलाड़ियों को सही समय पर अवसर मिलने चाहिए। उनका मानना है कि विश्वकप मे कोचिंग स्टाफ ने अनुभव को ही तरजीह दी जो काम नहीं आया, और प्रदर्शन में निरंतरता न होने से भारत ने सर्वश्रेष्ठ अवसर गंवा दिया, क्योंकि हर 10 मिनट में रक्षापंक्ति डगमगा गयी। वहीं पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कप्तान वासुदेवन भास्करन ने भारतीय फॉरवर्ड लाइन की गुणवत्ता पर निराशा व्यक्त की, यह कहते हुए कि पिछले चार सालों में किसी भारतीय फॉरवर्ड को अच्छा खेलते नहीं देखा। उन्होंने टीम की रणनीति पर भी सवाल उठाए। भास्करन ने भी कहा है कि हमने नए खिलाड़ियों को अवसर ही नहीं दिए। उन्होंने भारतीय चयन प्रक्रिया पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि हम पिछले रिकॉर्ड और आंकड़ों के आधार पर ही टीम चुन लेते हैं। भास्करन ने सुझाव दिया कि कम से कम छह जूनियर खिलाड़ियों को प्रो लीग में आजमाया जाना चाहिए था। वहीं, हॉकी दिग्गज परगट सिंह का मानना है कि भारतीय हॉकी का आंतरिक ढांचा इतना कमजोर है कि नई प्रतिभाएं निकल ही नहीं पातीं। उन्होंने अच्छी घरेलू प्रतियोगिताओं के अभाव को इसका मुख्य कारण बताया, पुराने टूनार्मेंटों जैसे बेटन कप, आगा खान कप और बॉम्बे गोल्ड कप के खत्म होने पर अफसोस जताया, जिनसे पहले अच्छी प्रतिभाएं निकलती थीं। परगट ने यह भी जोड़ा कि अगर नए खिलाड़ियों को मौका देना था, तो इस बदलाव की शुरूआत दो साल पहले ही कर देनी चाहिए थी। एक अन्य ओलंपियन ने कहा कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप जीतने से ही खुद का आकलन कर लिया जाता है, जबकि यूरोपीय टीमों के सामने प्रदर्शन में वह विफल रहती है।

सेंसेक्स 77422, निफ्टी में गिरावट, रुपये ने शुरूआती नुकसान से वापसी की

मुंबई। 27 अगस्त - वैश्विक अनिश्चितता से घरेलू बाजारों में बृहस्पतिवार को शुरूआती कारोबार में गिरावट, सेंसेक्स 45.17 अंक टूटकर 77,422.70 पर खुला, थोड़ी देर में 108.80 अंक गिरकर 77,368.68 पर घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में बृहस्पतिवार को शुरूआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई।

वैश्विक अनिश्चितता से बाजार की धारणा प्रभावित हुई है। बीएसई सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 45.17 अंक टूटकर 77,422.70 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 6.40 अंक फिसलकर 24,202.45 अंक पर आ गया।

थोड़ी ही देर में सेंसेक्स 108.80 अंक की गिरावट के साथ 77,368.68 अंक पर और निफ्टी 26.15 अंक टूटकर 24,189.70 अंक पर कारोबार करने लगा। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर सबसे अधिक गिरावट में रहे। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज फाइनेंस के शेयर में बढ़त दर्ज की गई।

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कम्पोजिट बढ़त में रहे जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल का भाव वायदा कारोबार में 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 87.45 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 502.63 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। सेंसेक्स बुधवार को 183.15 अंक और निफ्टी 126.80 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था।

रुपया शुरूआती कारोबार में चार पैसे चढ़कर 95.40 प्रति डॉलर

रुपया शुरूआती नुकसान से उबरते हुए बृहस्पतिवार को सुबह के कारोबार में चार पैसे की बढ़त के साथ 95.40 प्रति डॉलर पर आ गया। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.50 प्रति डॉलर पर खुला। फिर टूटकर 95.52 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले आठ पैसे की गिरावट है।

हालांकि, घरेलू मुद्रा ने जल्द ही नुकसान की भरपाई की और चार पैसे की बढ़त के साथ 95.40 प्रति डॉलर पर कारोबार करने लगा। रुपया मंगलवार को 26 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.44 पर बंद हुआ था। ईद-ए-मिलाद के अवसर पर बुधवार को भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार बंद था। इस बीच, दुनिया की छह मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दशार्ने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.14 पर रहा।

महंगा हुआ चावल: दाम में 15 फीसदी उछाल, निर्यात ने फिर भी पकड़ी रफ्तार

दाल खरीद के लिए खुलेंगे 500 केंद्र : 15% बढ़े दाम तीन हफ्ते में

नई दिल्ली। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में हालिया तेजी के बीच भारत के निर्यात कारोबार में भी मजबूती देखने को मिली है। नवंबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान बासमती और गैर-बासमती चावल की विदेशों में आपूर्ति 47.9 लाख टन रही। इसी अवधि में खुदरा बाजार में कई किस्मों के दाम बढ़े, जिसमें प्रीमियम बासमती सबसे अधिक महंगा हुआ। उधर, दलहन किसानों को फसल बेचने में सुविधा देने के लिए नैफेड और एनसीसीएफ देशभर में 500 नए खरीद केंद्र शुरू करने की तैयारी में हैं।

एक तरफ जहां देश में चावल के दाम में तेजी आ रही है, वहीं इसके निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 26 प्रमुख उपभोक्ता देशों को भारत का चावल निर्यात सिर्फ पांच महीनों तीन साल की नई उचाई पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच बासमती और गैर-बासमती चावल का कुल निर्यात 23,476 करोड़ रुपये और 47.9 लाख टन तक पहुंच गया।

पश्चिम एशिया संकट के कारण खाड़ी क्षेत्रों में चावल का आयात घट गया है। इसके बावजूद भारत का निर्यात प्रभावित नहीं हुआ है। भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि (नवंबर-मार्च) के औसत की तुलना में निर्यात मूल्य में 1.1 प्रतिशत और मात्रा में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

पिछले दो-तीन हफ्तों में चावल की खुदरा कीमतों में करीब 15 फीसदी की तेजी आई है। कई किस्मों के चावल 15-20 रुपये प्रति किलो तक महंगे हो गए हैं। सबसे अधिक तेजी प्रीमियम बासमती में देखी जा रही है। इसका भाव 85 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 110 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। साधारण और परमल चावल की किस्मों में भी प्रति क्विंटल 100 से 500 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।

दालों की खरीद के लिए खुलेंगे 500 नए केंद्र

दलहन उत्पादकों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने और बिक्री की परेशानियों से बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड दोनों मिलकर देशभर में 500 नए केंद्र खोलेंगे। ये दोनों एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधा दालों की खरीद करेंगी। नैफेड के प्रबंध निदेशक दीपक कुमार के मुताबिक, खरीफ सीजन की दालें जल्द बाजार में आने वाली हैं। इन केंद्रों पर अरहर के साथ ही चना और उड़द जैसी प्रमुख दालों की खरीद होगी। दाल उत्पादन वाले राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल हैं। नैफेड देश के करीब 50 जिलों में किसानों के बीच अभियान चलाकर पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएगा।

दूसरी छमाही में रियल एस्टेट-आईटी में बंपर नौकरियों के आसार

एफएमसीजी दूसरे स्थान पर; कहां ज्यादा मौका?

मुंबई। एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि साल की दूसरी छमाही में रियल एस्टेट और आईटी में भर्ती बढ़ सकती है। एफएमसीजी सेक्टर भी आगे रहेगा। क्या रोजगार बाजार में तेजी लौटने वाली है?

भारत के जॉब मार्केट में 2026 की दूसरी छमाही में भी नए रोजगार सृजन की अच्छी उम्मीद है। नौकरी डॉट कॉम का दावा है कि इस अवधि में भर्तियां जारी रहेंगी और रियल एस्टेट व आईटी सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार पैदा होंगे। कंपनी के हायरिंग आउटलुक सर्वे 2026 के मुताबिक, रियल एस्टेट में 86 फीसदी, एफएमसीजी में 85 फीसदी और आईटी क्षेत्र में 83 फीसदी एचआर लीडर्स ने नई नौकरियों के सृजन की संभावना जताई है।

आईटी सेक्टर का आंकड़ा पहली छमाही के 79 फीसदी से बढ़कर अब और मजबूत हुआ है। भर्ती के लिहाज से बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग और नई तकनीक से जुड़ी भूमिकाओं की मांग सबसे अधिक रहने का अनुमान है। योग्य लोगों का चयन बड़ी चुनौती : सीआईआई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की संख्या और उनके कार्यक्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती योग्य उम्मीदवारों का चयन है। जीसीसी किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसे विदेशी ऑफिस हैं, जो वैश्विक स्तर पर तकनीकी और अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण कार्य संभालते हैं।

एआई से बड़ा खतरा नहीं

सर्वे में यह भी सामने आया कि एआई से फिलहाल नौकरियों पर कोई बड़ा खतरा नहीं है। 86% एचआर लीडर्स ने कहा कि एआई से निकट भविष्य में बड़ी छंटनी की संभावना नहीं है।

वहीं, 20% का अनुमान है कि एआई आईटी और बीएफएसआई सेक्टर में सर्वाधिक नए रोजगार पैदा करेगा। खासतौर पर मार्केटिंग और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में।

कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही कौशल वाले अभ्यर्थियों की कमी है। 31% एचआर लीडर्स ने इसे प्रमुख समस्या बताया।

उनका कहना है कि नए कौशल तेजी से उभर रहे हैं और पुराने की उपयोगिता कम हो रही है, उन्हें नया कौशल सीखने की जरूरत है।

महत्वपूर्ण ख़बर

बाबा महाकाल की कृपा से सिंहस्थ-2028 का आयोजन भव्य और दिव्य होगा

■ भोपाल। बाबा महाकाल की कृपा से सिंहस्थ-2028 महापर्व का आयोजन भव्य, दिव्य, अद्भुत और अलौकिक होगा। सिंहस्थ के दृष्टिगत उज्जैन में किए जा रहे विकास कार्यों से महापर्व के पूर्व उज्जैन का सुंदर और सुव्यवस्थित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल के दायित्व ग्रहण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के लिए संत, प्रशासन, संगठन सभी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संत-महात्माओं के मार्गदर्शन में शासन-प्रशासन द्वारा सिंहस्थ महापर्व के लिए श्रद्धालुओं एवं साधु-संतों की सुविधा और सेवा के लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मंत्रालय कर्मचारियों ने किया अभिनंदन

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं, अब पदोन्नति का यह क्रम साल दर साल चलता रहेगा। इस साल सभी विभागों में पदोन्नति के लिए डीपीसी प्रारंभ होने वाली है। सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पारदर्शी निर्णय और दृढ़ संकल्प ही सुशासन का आधार स्तंभ है। कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार सभी कल्याणकारी निर्णय लेने के लिए सदैव तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कर्मचारियों बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मोहन कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट फोरलेन पर लगाई मुहर

3,961 करोड़ की लागत से होगा तैयार, कई प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मोहन कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार ने सिवनी और बालाघाट के फोरलेन निर्माण पर मुहर लगा दी। अब सिवनी और बालाघाट के लोगों का सफर आसान होने जा रहा है। यह अभी यह टू-लेन मार्ग है, जो कि कई जगह घुमावदार भी है। इस सड़क के बार-बार खराब होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। यही वजह है कि 91 किलोमीटर के सफर में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यह फोरलेन सड़क बनने के बाद यह सफर लगभग दो घंटे में पूरा हो जाएगा। इससे लोगों को आने-जाने में काफी आसानी मिलेगी। इस सड़क के फोरलेन

बनने से दोनों शहरों के बीच रहने वाले हजारों परिवारों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। यानी लगभग पांच लाख राहगीरों को इसका फायदा होगा। आसपास के क्षेत्रों को जोड़ें तो 8 से 10 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

हादसों में आएगी कमी

इसके फोरलेन बनने से छात्रों, मरीजों, किसानों और नौकरी या कारोबार के लिए आने-जाने वालों का समय बचेगा। सड़क बनने से हादसों में भी कमी आएगी। सबसे खास बात यह है कि इलाज और पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में आने-जाने वाले लोगों को समय पर पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। इस स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए सरकार ने 3961 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। फोरलेन का काम हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर होगा। यह फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और 543 को भी जोड़ेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश की 22 प्रमुख सड़कों का मालिकाना हक एमपीआरडीसी को देने का निर्णय भी लिया है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इसके बदले एमपीआरडीसी राज्य सरकार को अपनी अंश पूंजी जारी करेगा। इन सड़कों से मिलने वाला टोल और अन्य राजस्व एमपीआरडीसी की आय माना जाएगा। इससे निगम कर्ज के ब्याज और मूलधन का भुगतान करेगा। सिवनी-बालाघाट सड़क बनने से इन इलाकों के पर्यटन को भी काफी फायदा मिलने वाला है। फोरलेन सड़क से कान्हा और पेंच जैसे पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस मार्ग में लगभग 13 किमी का कान्हा कॉरिडोर भी शामिल रहेगा।

कॉरिडोर और अंडरपास को जोड़ा जाएगा

इसमें लगभग 3 किमी हिस्सा अंडरपास भी होगा। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कॉरिडोर और अंडरपास को जोड़ा जाएगा। 91 किमी मार्ग में कुछ बायपास भी बनाए जाएंगे। इससे भीड़ वाले हिस्सों में यातायात का दबाव कम करने और सफर भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा, इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण के लिए एमपीआरडीसी को 4,600 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज लेने की सरकारी गारंटी दी जाएगी। यह कर्ज नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस (एनआईडीए) से लिया जाएगा। इनमें भोपाल-विदिशा फोरलेन, इंदौर-देपालपुर, मंदसौर-सीतामऊ और पूर्वी भोपाल बाईपास को 4 से 6 लेन करने का काम शामिल है।

धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के लिए 244 पद मंजूर

मोहन कैबिनेट में उज्जैन में स्थापित होने वाले धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के लिए 244 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें 154 नियमित, एक संविदा और 89 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 31 जिलों में रहेगा।

एमपी में साइबर ठगी का अजब नियम

500 रुपये की रकम वापस लेने के लिए भी देना होगा 1000 रुपये का बॉन्ड

भोपाल। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को अपनी ही लूटी हुई रकम वापस पाने में एक अजीबोगरीब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के बाद ठगों के बैंक खातों में होल्ड (फ्रीज) की गई राशि लौटाने की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए मध्य प्रदेश में पीड़ितों को 1000 रुपये का क्षतिपूर्ति बॉन्ड देना पड़ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर किसी पीड़ित को महज 500 रुपये का रिफंड भी लेना है, तब भी उसे 1000 रुपये का स्टाम्प खरीदना ही होगा।

स्टाम्प कानून की बाध्यता बन रही बाधा

यह पूरी समस्या 'इंडियन स्टाम्प एक्ट-1899' के नियमों के कारण पैदा हुई है। इस एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में क्षतिपूर्ति बॉन्ड के लिए 1000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी अनिवार्य है। वर्तमान एसओपी में यह स्पष्टीकरण नहीं है कि कितनी रकम की वापसी पर कितने मूल्य का स्टाम्प देना होगा। इसी कानूनी पेंच के कारण जिन लोगों की कम राशि ठगी गई है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया आर्थिक रूप से अव्यावहारिक साबित हो रही है।

राजस्थान और कश्मीर ने दी राहत, मप्र में भी प्रस्ताव लंबित

इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने यहां क्षतिपूर्ति बॉन्ड की राशि को घटाकर 200 रुपये कर दिया है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों ने भी इसमें कटौती कर पीड़ितों को राहत दी है। इस तर्ज पर मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस ने भी राज्य के गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बॉन्ड की राशि को घटाकर 100 रुपये करने की सिफारिश की गई है। गृह विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा।

आखिर क्यों भरवाया जाता है यह बॉन्ड?

अधिकारियों के अनुसार, क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरवाने का मुख्य उद्देश्य कानूनी जटिलताओं से बचना है। अगर पीड़ित को पैसे वापस मिलने के बाद भविष्य में कोई दूसरा दावेदार अदालत पहुंच जाता है। कोर्ट किसी अन्य वैधानिक कारण से वह रकम वापस मांगता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति जवाबदेह होगा, जिसे रिफंड मिला है।

इंदौर में दूध के रेट 65 रुपये करने की मांग

दूध उत्पादक किसानों ने खोला मोर्चा

इंदौर। इंदौर जिले में एक सितंबर से दूध की नई खरीदी दर तय होने से पहले दूध उत्पादक किसानों ने 65 रुपये प्रति लीटर खरीदी मूल्य की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किसान शोषण विरोधी मंच के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्टर और संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

किसानों का कहना है कि पशुपालन और दूध उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें इसके अनुपात में दूध का मूल्य नहीं मिल रहा है। दरअसल, ज्ञापन सौंपने से पहले बायपास स्थित झालरिया में दूध उत्पादक किसानों की बैठक हुई थी। इसमें दिलीप सिंह पवार, महेंद्र सिंह, लाखन सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि दूध उत्पादन की वास्तविक लागत और किसानों की मेहनत को देखते हुए सरकार के सामने 65 रुपये प्रति लीटर खरीदी मूल्य की मांग रखी जाएगी। इसी मांग को लेकर मंगलवार को ज्ञापन सौंपा गया। दूध व्यापारियों का कहना है कि किसानों को फैट के आधार पर करीब 9.50 रुपये प्रति फैट की दर से भुगतान किया जा रहा है। आगामी दिनों में दूध के भाव को लेकर बैठक होगी। इसमें खरीदी दर बाजार मूल्य के साथ उत्पादन की वास्तविक लागत को आधार बनाकर तय की जाए।

किसानों ने कहा कि पशुओं की कीमत के साथ खली-भूसा, चारा, दवाइयों और मजदूरी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद गांवों के दूध उत्पादक किसानों को व्यापारियों से करीब 52 से 55 रुपये प्रति लीटर ही मिल रहे हैं। किसानों के अनुसार, मौजूदा दर में दूध उत्पादन की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में खली 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है और भैंस भी डेढ़ से पौने दो लाख रुपये तक मिल रही है। मजदूरी, भूसा, बिजली और डॉक्टर व दवाइयों का खर्च भी बढ़ चुका है।

बाजार में अधिक दाम पर बिक्री

किसानों ने खरीद और बिक्री मूल्य के अंतर पर भी सवाल उठाए। किसान शेरसिंह और महेंद्र सिंह का कहना है कि गांवों में जिस दूध के लिए 52 से 55 रुपये प्रति लीटर मिल रहे हैं, वही दूध शहर में उपभोक्ताओं को 65 से 70 रुपये प्रति लीटर तक बेचा जा रहा है। किसानों के अनुसार, इस अंतर में उत्पादकों को पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है।

इंदौर में बांबे अस्पताल के सर्विस रोड पर फंसी थी शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कार, अब वहीं बैठकर किया प्रदर्शन

इंदौर। बांबे अस्पताल की सर्विस रोड की बदहाली का शिकार मंगलवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे स्वयं हो गए थे। यहां से गुजरते समय उनकी कार कीचड़ में फंस गई थी। इसके बाद चौकसे ने वीडियो जारी कर बदहाल सड़क के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जिम्मेदार ठहराया।

इधर बुधवार को वे अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर

पहुंची और कीचड़ से भरी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया।

चौकसे ने कहा कि किसी काम से जा रहे थे, तभी सर्विस रोड पर जमा गहरे कीचड़ और गड्ढों में कार के पहिए फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार बाहर निकाली गई। कार कीचड़ से लथपथ हो गई और उन्हें भी परेशानी हुई।

सड़क कागजों पर ही बन रही

उन्होंने कहा कि दो साल पहले ड्रेनेज लाइन डालने के लिए इस सड़क को खोदा गया था। तब से यह सड़क कागजों पर ही बन रही है। हकीकत में एक इंच भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा- ह्यजब मेरी कार ही कीचड़ में फंस सकती है, तो सोचिए रोज यहां से गुजरने वाले हजारों दोपहिया वाहन चालकों का क्या हाल होता होगा। हर दिन लोग यहां फिसलकर गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं।

चौकसे ने कहा कि पोस्टर पर विकास का दावा करने वाले महापौर को दो साल से खोदकर छोड़ी गई यह सड़क दिखाई नहीं दे रही। उनके नेतृत्व में टूटी-फूटी और अधूरी सड़कों से ही इंदौर की पहचान बन गई है। भाजपा की परिषद का कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन शहर की सड़कों की हालत जस की तस है।

अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचे, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में प्रभावी सुधार लाया जा सके। मंत्री श्री नागर ने मंत्रालय में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। मंत्री श्री चौहान ने भिंड, मुरैना, शाजापुर और विदिशा में स्वीकृत कन्या छात्रावासों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

आमजन के काम हेल्प लाइन तक पहुंचने से पहले हो जाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आम जनता से जुड़े कार्यों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। आमजन के कार्य हेल्प लाइन तक पहुंचने से पहले ही पूरे हो जाएं, ऐसे प्रयास किए जाएं। जनता से जुड़े सभी प्राथमिक कार्यों का समय पर निपटारा आवश्यक है। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान : 2026 के माध्यम से साप्ताहिक शिविर और संवाद के आयोजन प्रारंभ किए हैं। गत तीन सप्ताह में इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। त्योहार या अन्य कारणों से जब शुक्रवार को जन विश्वास अभियान के तहत शिविर और संवाद का आयोजन नहीं हो सके तो आगामी दिवस अर्थात शनिवार को यह कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एक विशेष बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन ने उत्तरदायी प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान : 2026 प्रारंभ किया है। इस अभियान के संचालन से बड़ी संख्या में आमजन के

लंबित कार्यों और समस्याओं का समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जन विश्वास अभियान की आगामी एक माह की तैयारी रखी जाए, ताकि जनता को संवाद और शिविर का पूरा लाभ प्राप्त हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजधानी में मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में बायोमैट्रिक अटैंडेंस की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। यह प्रदेश के जिलों में भी लागू की जाएगी। अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और समय पर कार्यों को पूर्ण करें, इस पर वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए अधिकार अभिलेखों के पंजीयन, जिला स्तर पर राजस्व और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी गठित करने और ग्राम की दखल रहित भूमि का चिन्हांकन का कार्य पूर्ण किया जाए। ग्रामीण आबादी को बैंक ऋण आसानी से मिले इसके लिए सभी को निःशुल्क रजिस्ट्री का लाभ दिलवाने की अभियान के संचालन के लिए रूपरेखा तैयार कर अंतिम रूप दिया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि घोषित कर भूमिहीनों को आवास पट्टे प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया संचालित की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नर्मदा समग्र मिशन (नमन) के गठन और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

इंदौर में रांग साइड से आई बाइक के हैंडल में फंसा महिला का बैग

झटके से सड़क पर गिरने से मौत

इंदौर। राखी मनाने पति और बेटे के साथ मायके (उज्जैन) जा रही 30 वर्षीय महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। बायपास पर गलत दिशा से आए बाइक सवार के हैंडल में महिला का बैग अटक गया। इससे दोनों बाइक का संतुलन बिगड़ा और महिला सड़क पर गिर गई। सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।

महिला की पहचान तिल्लौर निवासी 30 वर्षीय पूजा पाटीदार के रूप में हुई है। वह पति निर्मल पाटीदार और आठ वर्षीय बेटे शिवाय के साथ मायके जा रही थी। पूजा बाइक पर पीछे बैठी थी और उसके हाथ में कपड़ों से भरा बैग था। बायपास (बेस्ट प्राइस के पास) पर दूसरी बाइक पर सवार युवक गलत दिशा से ओवरटेक करते हुए निकला। इसी दौरान पूजा के हाथ में मौजूद बैग उस बाइक के हैंडल में फंस गया। अचानक हैंडल में फंसे बैग के खिंचने से दोनों बाइक असंतुलित हो गईं और पूजा सड़क पर जा गिरी।

सिर में लगी गंभीर चोट, खून बहता रहा

जेठ प्रदीप के मुताबिक, बाइक पूजा को दूर तक घसीटते हुए ले गई थी। हादसे में पूजा के सिर में गहरी चोट आई। चोट इतनी गंभीर थी कि उसके मुंह, नाक और कान से खून निकलने लगा। पति निर्मल ने एंबुलेंस (108) से तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में राखी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। निर्मल खेती के साथ नमकीन कारखाने में गाड़ी चलाने का काम भी करता है। निर्मल और शिवाय को भी मामूली चोट आई है।

विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा से होगा विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त

भोपाल। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्र पुनर्निर्माण के महायज्ञ में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और हमारा मुख्य केंद्रबिंदु विद्यार्थी है, इसलिए उच्च शिक्षा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन विद्यार्थी के सर्वांगीण हित और विकास को ध्यान में रखकर होना चाहिए। शिक्षा केवल उपाधि प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल, व्यक्तित्व, संस्कार, नैतिक मूल्यों और जीवन-दृष्टि के निर्माण का माध्यम है। विद्यार्थियों को रोजगार एवं कौशल के लिए सक्षम बनाने के साथ उनमें मानवीय संवेदनाएं, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करना भी आवश्यक है। हमारा ध्येय केवल रोजगार प्राप्त करने वाली पीढ़ी तैयार करना नहीं, बल्कि ज्ञानवान, कुशल, संवेदनशील, चरित्रवान और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझने वाले श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए।

इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने एक हजार से ज्यादा मोडिफाइड साइलेंसर पर चलवाया रोड रोलर

इंदौर। इंदौर शहर के चौराहों और मुख्य मार्गों पर बेहतर यातायात प्रबंधन के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है।

यातायात पुलिस ने विजय नगर में मोडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट किया। आकस्मिक

चेकिंग कर तेज या लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों, मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज और कर्कश ध्वनि निकालकर आम जनता में भय पैदा करने वाले वाहन चालकों और हूटर लगे वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

मोडिफाइड साइलेंसर भी जब्त किये गये

बीते माह से यातायात प्रबंधन पुलिस के सभी अधिकारियों द्वारा यातायात प्रबंधन जोन के अंतर्गत आने वाले मुख्य मार्गों और चौराहों पर यातायात अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम बनाकर तेज और कर्कश ध्वनि वाले मोडिफाइड साइलेंसर एवं हूटर लगे वाहनों के विरुद्ध सघन जांच कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान मोडिफाइड साइलेंसर भी जब्त किए गए।

साइलेंसर लगाकर डराने की कोशिश

विजय नगर क्षेत्र में भी डीसीपी यातायात राजेश कुमार त्रिपाठी और यातायात के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जब्त एक हजार से ज्यादा साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट किया गया। डीसीपी त्रिपाठी ने कहा कि नियम विरुद्ध तेज और कर्कश ध्वनि वाले साइलेंसर लगाकर आम जनता में भय पैदा करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।